https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'काले धन की लड़ाई में सबसे ज्यादा युवाओं ने साथ दिया'

वर्ष-12, अंक-03, 01-15 फरवरी, 2017 (पाक्षिक) ₹20

दीनदयालजी के अंत्योदय विचार से प्रेरित है मोदी सरकार

व्यापक, सर्वसमावेशी और भविष्योन्मुखी है हमारा संविधान

भारत को जोड़ेगा डिजिटल इंडिया

विधानसभा चुनाव 2017 पर विशेष

पुरी (ओडिशा) में मां विमलांबा प्रतिष्ठा महोत्सव को संबोधित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 गरीबों को सशक्त बनाना मोदी सरकार का उद्देश्यः अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पटना (बिहार) के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 10 फरवरी को 'एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान' एवं चिति (प्रज्ञा प्रवाह की इकाई) के...

वैचारिकी

मानव की स्थिति और प्रगति 12

श्रद्धांजलि

दीनदयालजी की याद में 14

लेख

अभूतपूर्व बदलाव लानेवाली कृषि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन 16
व्यापक, सर्वसमावेशी और भविष्योन्मुखी है हमारा संविधान 18
स्वच्छ भारत मिशनः आगे की राह 20
भारत को जोड़ेगा डिजिटल इंडिया 22
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 82,708 करोड़... 23

साक्षात्कार

मोदी सरकार की कृषि समर्थित नीतियों से किसानों को लाभ पहुंचा 24

अन्य

ओआरओपी के तहत सरकार ने दिए 6,285 हजार करोड़ रुपए 09
'काले धन पर उठाए गए कठोर कदमों से विकास दर बढ़ेगी' 10
रबी की फसल की 616 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई 11
'भारतीय युवाओं ने कट्टरता का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है' 15
पांच राज्यों में चुनाव 26
3.81 लाख से अधिक ग्राहकों और 21,000 व्यापारियों ने... 28
मछुवारों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में सहायक 31

संगठनात्मक गतिविधियां

08 'जहां कांग्रेस वहां करप्शन, जहां भाजपा वहां विकास'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 23 जनवरी को वास्को और...

30 'गुरु गोबिंद सिंह ने अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों से देश पर बड़ा उपकार किया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 8 जनवरी को जबलपुर...

सरकार की उपलब्धियां

09 वित्त वर्ष 2017 में भारत की वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमानः संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर...

11 'एसईजेड इंडिया' एप का शुभारंभ

वाणिज्य सचिव ने 6 जनवरी को 'एसईजेड इंडिया' मोबाइल एप लॉन्च किया। वाणिज्य विभाग के एसईजेड प्रभाग ने अपनी...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@JPNadda

उत्तराखंड में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

@rsprasad

लगभग 99.6 युवाओं के पास आधार कार्ड है। इसका उपयोग कर पिछले 2 वित्तीय वर्ष में सरकार ने सब्सिडी का प्रभावी वितरण सुनिश्चित कर 36 हज़ार करोड़ रुपये की बचत की है।

@RajivPratapRudy

बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की केन्द्रीय योजनाओं में हाथ बटाएं। बालिकाओं को कुशल व सशक्त बनाएं, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ें #IndiaWithDaughters

@PiyushGoyal

घरों में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा व ईमानदार उपभोक्ताओं के लिये बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।

facebook

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर आपको बधाई। आने वाले वर्षों में अमेरिका को महान उपलब्धियों की ओर ले जाने के लिए शुभकामनाएं। भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की शक्ति हमारे साझा मूल्यों और साझा हितों में निहित है। भारत-अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और आपसी सहयोग की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने को आशान्वित हूं।

- नरेंद्र मोदी

गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों से देश पर बहुत बड़ा उपकार किया, उन्होंने देश को वीरता की प्रेरणा दी, स्वतंत्रता एवं आध्यात्मिकता का संदेश दिया, इस तरह की मिसालें इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आने वाले हजारों साल तक गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन न केवल सिखों के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि देश की रक्षा, भक्ति, साहित्य, धर्म और अपनी आत्मा की ऊंचाई के लिए जीने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए अक्षय प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

- अमित शाह

साभार: नई दुनिया

पाथेय

आज देश और हमारे संगठन के सामने जो ठोस चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए हमें भाजपा की विचारधारा के मूलमंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करते समय हमें अपने मन से ऐसी गलत धारणा को निकाल देनी चाहिए कि समन्वय केवल समझौते का एक नुस्खा है और इसलिए यह दुर्बल लोगों का मार्ग है। नहीं, यह शक्तिशाली लोगों का मार्ग है।

-कुशाभाऊ ठाकरे

परिवर्तनकारी हैं आगामी विधानसभा चुनाव

आगामी महीनों में पांच राज्य अपनी नई विधानसभा चुनने वाले हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 मार्च 2016 को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में लोग विभिन्न चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार चुनेंगे। यह एक बहुत ही बड़ा चुनावी कार्यक्रम है, जिससे आने वाले वर्षों के लिए इन राज्यों का भविष्य तय होना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भारत व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इन राज्यों का चुनाव इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी नीतियों से ये राज्य कितने प्रभावी एवं अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ पायेंगे। अब जबकि भारत विकसित देशों से कदम मिलाकर तीव्र विकास की आकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग विकास एवं सुशासन के पक्ष में मतदान करेंगे।

ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी सत्ताधारी दल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही हार मान ली हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। यह वही पार्टी है जिसने पांच वर्ष पूर्व अकेले चुनाव लड़ा था और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई थी। इन पांच वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि उसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को मजबूर होना पड़ा? पिछले पांच वर्षों का कुशासन, गुंडाराज एवं भ्रष्टाचार सपा का साये की तरह पीछा कर रहा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी बन गई है, जिसे जनता लगातार ठुकराती रही और अब सपा की साइकिल पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचना चाहती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सपा भी चुनावी–वैतरणी पार नहीं कर सकती। दोनों पार्टियों की छवि असामाजिक तत्वों, घोटालेबाजों एवं सत्ता के दलालों की पनाहगाह के रूप में बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के लोग न केवल सपा–बसपा कुशासन के चक्र को तोड़ना चाहते हैं, बल्कि परिवर्तन, प्रगति एवं विकास के नये युग की शुरुआत भी करना चाहते हैं। लोग अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस–सपा–बसपा ही प्रदेश के पिछड़ेपन, बदहाल कानून-व्यवस्था एवं पतनशील राजनीति के लिए जिम्मेदार हैं। जहां लोगों ने पिछली बार बसपा को ठुकराया था, वहीं इस बार उन्हें सपा–कांग्रेस को एक साथ ठुकराने का अवसर मिला है। कांग्रेस के साथ गठंबधन कर सपा ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह अपने दम पर जनता को मुंह नहीं दिखा सकती, लेकिन कांग्रेस को अपना दामन थमा कर उसने लोगों के नजर में अपनी स्थिति और भी बदतर बना ली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चमत्कारी नेतृत्व ने देश में नई आशा एवं विश्वास का संचार किया है। लोगों को अपने सपने साकार होते दिख रहे हैं। प्रदेशों में भी लोग जनकल्याण एवं जनसेवा को समर्पित सरकारें चुनने में अपना विश्वास जता रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री एवं राजग सरकार को हर ओर अद्भुत जनसमर्थन मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों में लोग विभाजनकारी एवं प्रतिगामी राजनीति को हटाकर विकास एवं सुशासन की राजनीति को चुनने को तत्पर हैं।

उत्तर प्रदेश के साथ–साथ उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में भी भाजपा के लिए सुनहरा अवसर है। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार जनता की अपेक्षा पर खरी उतरने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। भ्रष्टाचार, गुटबाजी एवं आपसी कलह ही प्रदेश में कांग्रेस की पहचान बन गई है। गोवा में सरकार के अच्छे कार्यों के कारण लोग भाजपा के प्रति उत्साहित हैं। पंजाब में अकाली दल–भाजपा एक विश्वसनीय गठबंधन के रूप में उभरा है, जिसने प्रदेश को नई ऊंचाइयां दी हैं। मणिपुर में लोग कांग्रेस को छोड़ नए विकल्प के रूप में भाजपा को देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के दूरदृष्टि नेतृत्व में भाजपा का विस्तार देश के कोने–कोने में हुआ है, तथा यह एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चमत्कारी नेतृत्व ने देश में नई आशा एवं विश्वास का संचार किया है। लोगों को अपने सपने साकार होते दिख रहे हैं। प्रदेशों में भी लोग जनकल्याण एवं जनसेवा को समर्पित सरकारें चुनने में अपना विश्वास जता रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री एवं राजग सरकार को हर ओर अद्भुत जनसमर्थन मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों में लोग विभाजनकारी एवं प्रतिगामी राजनीति को हटाकर विकास एवं सुशासन की राजनीति को चुनने को तत्पर हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

गरीबों को सशक्त बनाना मोदी सरकार का उद्देश्य: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पटना (बिहार) के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 10 फरवरी को 'एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान' एवं चिति (प्रज्ञा प्रवाह की इकाई) के तत्वावधान में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किया और लोगों से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता एवं विकास के लिए काम करने का आह्वान किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कार्यकाल तो छोटा ही था लेकिन संघ प्रचारक के रूप में काम करते-करते वे देश काल और सामाजिक जीवन के कई समस्याओं का निराकरण इतने अल्प समय में कर के गए हैं कि यदि किसी समस्या का समाधान किसी को पाना है तो वह पंडित दीन दयाल जी के जीवन, उनके आलेखों व भाषणों को पढ़ ले, वहीं से उसकी सारी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक दूरगामी चिंतक, मूर्धन्य विचारक और एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने कहा कि अंतर्विरोधों से भरे एक काल-खंड के मध्य भी पंडित जी ने समन्वय की राजनीति को बल देकर आगे बढ़ाने का काम किया।

श्री शाह ने कहा कि 'भारत एक जियो पॉलिटिकल नहीं, एक जियो कल्चरल राष्ट्र है' इस कल्पना को पहली बार विश्व के सामने यदि किसी ने रखने का काम किया तो पंडित दीनदयाल जी ने किया, उन्होंने बड़ी सहजता के साथ लोगों के सामने इस परिकल्पना को रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए यह गौरव की बात है कि मैं उस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस वर्ष पंडित दीनदयाल जी का जन्मशती वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेरे जैसे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का समय है। उन्होंने कहा कि गत सितम्बर में कालीकट (जहां दीनदयाल जी भारतीय जन संघ के अध्यक्ष बने थे, उसी शहर) में पंडित जी की जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके 'अंत्योदय' के विचार के आधार पर इस शताब्दी वर्ष को गरीब-कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों पर ही चल रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल

नेहरू जी के नेतृत्व में देश की नीतियां बनाने के लिए एक सर्वदलीय सरकार का गठन किया हुआ था, तब देश के कई बुद्धिजीवियों एवं मनीषियों को लगा कि देश के लिए जो नीतियां बन रही हैं, उसका मूल तो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, इसमें कहीं भी भारत की सभ्यता, संस्कृति व देश की माटी की सुगंध नहीं है, यदि इसी रास्ते पर देश चला तो देश काफी पिछड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों के बीच देश को एक वैकल्पिक विचारधारा देने के लिए श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्त्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि जन संघ की स्थापना के वक्त किसी ने दूर-दूर तक यह कल्पना भी नहीं की थी कि कभी म्युनिस्पैलिटी में भी जन संघ जीत हासिल कर पायेगी।

श्री शाह ने कहा कि जनसंघ एवं कांग्रेस के मूल विचारों में जो एक स्पष्ट अंतर है, वह यह है कि कांग्रेस इस देश का नवनिर्माण करना चाहती थी जबकि जनसंघ भारत की सभ्यता व संस्कृति की गौरवशाली विरासत के मार्ग पर चलते हुए देश का पुनर्निर्माण करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि जनसंघ का मानना था कि देश का जो पुराना था, वह तब भी सर्वोच्च था, आज भी सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भाषणों एवं आलेखों के माध्यम से राष्ट्र गौरव को जागृत करने का काम किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दल के सत्ता में आने पर सरकार चलाने के लिए वैचारिक आधार देने का काम भी पंडित दीन दयाल जी ने किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल जी ने पार्टी चलाने के लिए जो नियम बनाए थे, पार्टी की जो कार्यपद्धति बनाई थी, सिद्धांतों को सरलता से जिस प्रकार उन्होंने व्याख्यायित किया था, आज उसी का परिणाम है कि 10 सदस्यों के साथ शुरू हुई जनसंघ पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि विचारों का छोटा-सा जो बीज पंडित दीन दयाल जी ने बोया था, आज वह बटवृक्ष के रूप में खड़ा होकर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या व्यक्ति से समष्टि तक एकात्म भाव से जिस प्रकार का विकास का मॉडल पेश करने की बात हो - इन सारी चीजों को एकात्म मानव दर्शन के रूप में संजो कर उन्होंने देश एवं दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने उस वक्त जलवायु समस्या को गंभीरता से रखा था, जब बहुत लोग इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम उनके सिद्धांतों के अनुरूप चले होते तो आज ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या से हम चिंतित न होते।

श्री शाह ने कहा कि संगठन का दायित्त्व भी पंडित दीनदयाल जी ने बखूबी निभाया, संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री फिर जन संघ के अध्यक्ष रहे, जन संघ की कार्यप्रणाली की नींव डालने का काम जो उन्होंने किया, उसी नींव पर आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का विचार करने वाली पार्टी है, देश की चिंता करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल का परिचय क्या होता है- पार्टी का परिचय उसका सिद्धांत होता है, उसके किये गए आंदोलन होते हैं, उस आंदोलन से निकले हुए पार्टी के नेता होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सिद्धांतों को देखिये, हमारे आंदोलनों को देखिये- चाहे गोवा मुक्ति आंदोलन हो, हैदराबाद का आंदोलन हो, गौ-हत्या पर प्रतिबद्ध का आंदोलन हो, कच्छ सत्याग्रह हो, कश्मीर की मुक्ति का आंदोलन हो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का आंदोलन हो - हर आंदोलन के पीछे देश का विचार है, सांस्कृतिक एकता का राग है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई आंदोलन, कोई यात्रा किसी नेता को बड़ा करने के लिए नहीं बल्कि जन-जागृति फैला कर देश की समस्या के निवारण के लिए करते हैं, यह परिचय है भारतीय जनता पार्टी का।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती को गरीब-कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का बिलकुल सही फैसला किया क्योंकि जब तक हम देश के गरीब-से-गरीब व्यक्ति के जीवन को ऊपर नहीं उठाते हैं, तब तक हम देश को आगे लेकर नहीं जा सकते।

श्री शाह ने कहा कि दीनदयाल जन्मशती में विचार परिवार का हर कार्यकर्ता और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए आत्मचिंतन का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि हमें ऐसा संगठन बनाना है कि जिसकी आभा से पूरा विश्व इस प्रकार चकाचौंध हो जाए कि जिसके अंदर से सिद्धांतों की सुगंध बाहर आ सके, यदि हम ऐसे संगठन के माध्यम से देश को 'विश्वगुरु' के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो हमारे लिए पंडित दीनदयाल जन्मशती एक बहुत बड़ा मौक़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्मशती को गरीब-कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का बिलकुल सही फैसला किया क्योंकि जब तक हम देश के गरीब-से-गरीब व्यक्ति के जीवन को ऊपर नहीं उठाते हैं, तब तक हम देश को आगे लेकर नहीं जा सकते। ■

'जहां कांग्रेस वहां करप्शन, जहां भाजपा वहां विकास'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 23 जनवरी को वास्को और मडगांव (गोवा) में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से गोवा को एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गोवा में चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच है तो कुछ लोग अन्य बातें कर रहे हैं लेकिन मेरी नजर में गोवा चुनाव दो पार्टियों के बीच चुनाव नहीं बल्कि यह चुनाव स्थिरता व विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि यदि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में स्थिरता एवं विकास आयेगा लेकिन यदि कांग्रेस एंड कंपनी की सरकार बनती है तो हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा कि गोवा की जनता को ट्रांसपेरेंसी एवं करप्शन के बीच में चुनाव करना है। उन्होंने कहा कि गोवा की जनता कांग्रेस एंड कंपनी को चुनने की भूल कभी नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गोवा के विकास को ठप्प कर दिया था। उन्होंने कहा कि गोवा के युवाओं के रोजगार का मुख्य साधन माइनिंग इंडस्ट्री है जिसे ख़त्म करने का पाप कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के एक ही साल में धीरे-धीरे माइनिंग इंडस्ट्री को फिर से शुरू कर राज्य के युवाओं को रोजगार देने का काम भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जब गोवा की जनता से वोट मांगने आयें तो राज्य की जनता उनसे अरबों-खरबों की माइनिंग करप्शन के पाप पर जवाब जरूर मांगे। उन्होंने कहा लुई बर्गर घोटाले में चार्जशीट फ़ाइल हो रही है, इसमें कई कांग्रेस नेताओं के नाम हैं, कांग्रेस को इस पर भी जवाब देना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, जहां कांग्रेस है, वहां करप्शन है और जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां विकास - यही दोनों पार्टियों का चरित्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और अस्थिरता की जनक है। उन्होंने कहा कि गोवा के विकास का मुख्य कारण राज्य की जनता द्वारा बहुत समय बाद भाजपा को दिया गया पूर्ण बहुमत है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए कई काम किये हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम पर्रिकर जी के डिपार्टमेंट ने किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासन में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारे जवान सुरक्षित नहीं थे, उन्हें अपमानित किया जाता था। उन्होंने कहा कि उरी हमले में कायराना तरीके से हमारे सोये हुए जवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन इस बार केंद्र में कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और सेना के वीर जवानों के शौर्य के फलस्वरूप पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया किया गया - यह परिचय है मोदी सरकार का।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गोवा की जनता को यह तय करना है कि गोवा में अस्थिरता, बेरोजगारी, करप्शन लाना है या फिर विकास और स्थिरता। उन्होंने कहा कि यदि गोवा को विकास के क्षेत्र में आगे ले कर जाना है, गोवा को एक मॉडल स्टेट बनाना है, तो मैं आज इस मंच से गोवा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार गोवा की जनता साधारण बहुमत नहीं, भाजपा को दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने का मौक़ा दें, हम गोवा को एक मॉडल स्टेट बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। ■

ओआरओपी के तहत सरकार ने दिए 6,285 हजार करोड़ रुपए

केंद्र सरकार ने देश के सैनिकों के लिए ओआरओपी स्कीम के तहत अब तक 6,285 करोड़ रुपये दे चुकी है। इस बात की जानकारी रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने दी। डॉ. भामरे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) योजना, लागू कर दी, जिसकी मांग कार्यान्वयन के लिए पिछले 40 से अधिक वर्षों से लंबित थी। 27 दिसंबर, 2016 को ओआरओपी बकाया के भुगतान की मौजूदा स्थिति इस प्रकार हैंः- प्रथम किस्त के रूप में 3,994.49 करोड़ रुपये 19,69,385 भूतपूर्व सैनिक को वितरित कर दिये गये हैं, जबकि दूसरी किस्त के तौर पर 2,290.72 करोड़ रुपये की राशि 15,54,849 भूतपूर्व सैनिकों को वितरित कर दी गयी है।

दिल्ली छावनी में 14 जनवरी को सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. भामरे ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिक सशस्त्र बल परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमारे मूल्यों और संस्कृति के पालक हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पूर्ण सम्मान दें, क्योंकि वे वर्तमान और अतीत के मध्य की एक अटूट कड़ी हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त सैनिकों उनकी विधवाओं को यह आश्वासन दिया कि केंद्र, राज्य सरकारें और सभी सेवा मुख्यालय उनकी देखभाल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

डॉ भामरे ने अपने संबोधन के दौरान सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। पिछले वर्ष दिल्ली छावनी में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए निदेशालय की स्थापना और प्रत्येक क्षेत्र और उप-क्षेत्र स्तर पर उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उन्होंने उल्लेख किया। मंत्री महोदय ने कहा कि पेंशन अनुदान, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के लिए रैलियों का आयोजन किया जाता है और पिछले वर्ष ऐसी 102 रैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने कहा है कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दों और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को व्यक्त करने और उनके निवारण की मांग के लिए आर्मी वेटरन पोर्टल जैसे उपलब्ध अधिकारिक माध्यमों का उपयोग करें।

मंत्री महोदय ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों के कौशल विकास पर बल दिया, ताकि वे अपने कैरियर में एक नई पारी की शुरूआत करके राष्ट्र के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए संपूर्ण भारत और नेपाल में ईसीएचएच अपने पॉलीक्लिनिकों के माध्यम से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। ■

वित्त वर्ष 2017 में भारत की वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमानः संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 17 जनवरी को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत निजी खपत और महत्वपूर्ण घरेलू सुधारों का फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रकाशन है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दशा व दिशा पर प्रकाश डालती है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि मजबूत निजी उपभोग के कारण वित्त वर्ष 2017 में भारत का विकास दर 7.7 प्रतिशत और वर्ष 2018 में 7.6 प्रतिशत की रहेगी। वहीं चीन की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2017 व 2018 में 6.5 फीसदी पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है।

अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारत में नोटबंदी का अल्पावधि में उपभोक्ता खर्च पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था 7.6 या फिर 7.7 प्रतिशत विकास दर की ओर लौट आएगी। ■

काले धन पर उठाए गए कठोर कदमों से विकास दर बढ़ेगी: अरुण जेटली

दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर होने के बावजूद अपने वृहद आर्थिक बुनियादी तत्वों में बेहतरी के बल पर भारत की स्थिति आज अपेक्षाकृत काफी मजबूत है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा समानांतर अर्थव्यवस्था एवं कर चोरी केंद्रीय निजात पाने के लिए उठाये गये कदमों का आगे चलकर जीडीपी और राजकोषीय मजबूती दोनों पर ही सकारात्मक असर पड़ने की आशा है। वित्त मंत्री ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में ये बातें कहीं।

एफएसडीसी की बैठक में सभी वित्तीय नियामकों और वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में जिन गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, उनमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर.पटेल, वित्त सचिव श्री अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) में सचिव श्री शक्तिकांत दास, राजस्व विभाग में सचिव डॉ. हसमुख अधिया, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) में सचिव सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में सचिव श्री नीरज कुमार गुप्ता, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन, सेबी के चेयरमैन श्री यू.के. सिन्हा, आईआरडीएआई के चेयरमैन श्री टी.एस.विजयन, पीएफआरडीए के चेयरमैन श्री हेमंत जी कांट्रैक्टर और भारत सरकार एवं वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे।

इस अवसर पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अर्थव्यवस्था की

हालत पर एक प्रस्तुति दी। परिषद ने अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मसलों एवं इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों की समीक्षा की और इसके साथ ही यह बात नोट की कि अपने वृहद आर्थिक बुनियादी तत्वों में बेहतरी के बल पर भारत की स्थिति आज अपेक्षाकृत काफी मजबूत नजर आती है। परिषद ने यह बात भी नोट की कि समानांतर अर्थव्यवस्था और काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का आगे चलकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राजकोषीय मजबूती दोनों पर ही सकारात्मक असर पड़ने की आशा है। ■

भारत और मॉरीशस के बीच कृषि-उद्योग, मत्स्यपालन और डेयरी पर समझौता

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह और व्यापार, उद्यम और सहकारी समिति मंत्री, मॉरीशस सरकार, श्री सुमिल दत्त भोलहा ने 16 जनवरी को सहकारी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों ही देशों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने में मदद करेगा, जिससे हजारों मॉरीशसवासियों को लाभ पहुंच सकता है। भारत ने कृषि उद्योग,मत्स्यपालन और डेयरी के क्षेत्र में मॉरीशस के साथ अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान का प्रस्ताव दिया।

दोनों मंत्रियों ने भारत और मॉरीशस के बीच साझा सांस्कृतिक और पूर्वजों के समय से बने संबंध,जो कि समय गुजरने के साथ मजबूत हुए हैं और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, पर संतुष्टि जताई तथा यह विचार व्यक्त किया कि समय-समय पर दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरों के जरिए पारस्परिक संबंधों में और अधिक मजबूती आई है। ■

रबी की फसल की 616 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई

विमुद्रीकरण से रबी की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह बात बुवाई की गई रबी फसलों के कुल क्षेत्रों से साबित हो जाती है। राज्यों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 13 जनवरी, 2017 को बुवाई की गई रबी फसलों का कुल क्षेत्र 2016 के लिए 581.95 लाख हेक्टेयर की तुलना में 616.21 लाख हेक्टेयर है। 309.60 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 14.92 लाख हेक्टेयर में चावल, 155.35 लाख हेक्टेयर में दालों, 54.87 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज और 81.47 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुवाई/रोपाई की गयी है। अब तक हुई बुवाई का क्षेत्र और पिछले वर्ष के दौरान इस समय तक हुई बुवाई इस प्रकार हैः

फसल	2016-17 में बुवाई क्षेत्र	2015-16 में बुवाई क्षेत्र
गेंहू	309.60	289.07
चावल	14.92	19.48
दालें	155.35	139.93
मोटा अनाज	54.87	58.40
तिलहन	81.47	75.06
कुल	616.21	581.95

लाख हेक्टेयर

'एसईजेड इंडिया' एप का शुभारंभ

वाणिज्य सचिव ने 6 जनवरी को 'एसईजेड इंडिया'मोबाइल एप लॉन्च किया। वाणिज्य विभाग के एसईजेड प्रभाग ने अपनी व्यापक ई-गवर्नेंस पहल अर्थात एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए मोबाइल एप का विकास किया है। वाणिज्य सचिव ने एप लॉन्च किया तथा कहा कि यह एप एसईजेड इकाईयों और डेवलपरों को सूचनाओं को आसानी से प्राप्त करने तथा एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर उनकी लेनदेन को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करेगा।

अब एसईजेड डेवलपर और इकाईयां एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपने लेनदेनों को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और एसईजेड इंडिया मोबाइल एप के जरिए उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह एप एसईजेड डेवलपरों, इकाईयों, अधिकारियों एवं अन्य लोगों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने हेतु एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

इस एप के चार खंड हैंः एसईजेड इनफॉरमेशन, एसईजेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ट्रेड इनफॉरमेशन एवं कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इन चारों खंडों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं : -

एसईजेड इनफॉरमेशन- यह एसईजेड अधिनियम 2005, एसईजेड नियम 2006, एमओसीआई परिपत्र, एसईजेड एवं इकाईयों के विवरण आदि का एक सार-संग्रह है। यह उपरोक्त सभी पहलुओं पर व्यापक ताजा विवरण प्रस्तुत करता है।

ट्रेड इनफॉरमेशन- यह प्रावधान विदेश व्यापार नीति, प्रक्रियाओं की लघु पुस्तिका, ड्युटी कैलकुलेटर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिसूचनाएं एवं एमईआईएस दरों जैसी महत्वपूर्ण सूचना / टूल्स तक पहुंच प्रदान करता है।

कॉन्टेक्ट डिटेल्स- इस खंड में सभी विकास आयुक्त कार्यालयों, डीजीएफटी, डीजी प्रणाली, डीजीसीआई एवं एस तथा एसईजेड ऑनलाइन के संपर्क विवरण दिए गए हैं।

एसईजेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन- यह एक गतिशील उपविकल्प सूची है जो एंट्री बिल / शिपिंग बिल प्रोसेसिंग स्टेटस को ट्रैक करता है तथा उनका सत्यापन भी करता है। यह एप आईसीईजीएटीई की ईडीआई प्रणाली में 'एंट्री बिल / शिपिंग बिल' के समेकन तथा प्रोसेसिंग के स्टेटस को ट्रैक करने में आयातकों / निर्यातकों की मदद भी करता है। ■

मानव की स्थिति और प्रगति

भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता एवं मौलिक विचारक थे। देशभर में उनकी जन्मशताब्दी वर्ष (2016-17) के अवसर पर संगोष्ठियों का आयोजन एवं पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। कमल संदेश में भी हम लगातार उनके द्वारा लिखे गए विचारशील लेखों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर हम राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका 'पांचजन्य'(1 अक्तूबर, 1949) में प्रकाशित उनके लेख का पुनर्प्रकाशन कर रहे हैं।

दीनदयाल उपाध्याय

मानव की स्थिति और प्रगति उसकी जयिष्णु और सहिष्णु प्रवृत्ति के सामंजस्य पर ही निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा दूसरों पर प्रभाव डालने की, उन पर विजय पाने की रहती है तथा अपने व्यक्तित्व को प्रभावी एवं विजयी बनाने के लिए वह सतत् प्रयत्नशील रहता है। उसकी दौड़-धूप इसलिए होती रहती है, किंतु इस प्रकार की प्रबल आकांक्षा का परिणाम दूसरों का विनाश एवं इस प्रकार उनके द्वारा होने वाले सत्य के आविष्कार की संभावना भी समाप्त न हो। इसके लिए मानव ने यह भी आवश्यक समझा है कि वह दूसरों के मतों का आदर करें तथा उसे सत्य मानकर चले। इस भावना ने ही सहिष्णुता की प्रवृत्ति को जन्म दिया है।

विश्व में भारतवर्ष अपनी चरम कोटि की सहिष्णुता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम में सहिष्णुता की भावना को बहुत ही निकट भूत में अनुभव किया है तथा जनतंत्र के नाम पर उसका विकास करने का प्रयत्न किया है। फिर भी उसके जीवन में असहिष्णुता इतनी समा गई है कि सहिष्णुता का राग अलापते रहने पर भी किसी न किसी प्रकार असहिष्णुता प्रकट हो ही जाती है। अंग्रेजी, फ्रांसीसियों और डचों की साम्राज्यवादी भावनाएं, एशिया के लोगों पर किए गए अत्याचार, ईसाई धर्म के अतिरिक्त सब धर्मों को ओछा मानकर उनके साथ किया हुआ व्यवहार, अंग्रेजों का श्वेत मानव का बोझा अफ्रीका में हब्शियों एवं अन्य अश्वेतों के लिए बनाए गए कानून, अमेरिका में नीग्रों एवं रेड इंडियनों के प्रति किया गया बरताव तथा जर्मनी, इटली, रूस आदि देशों में उत्पन्न होनेवाली फासिस्ट मनोवृत्ति एवं हर पच्चीस वर्ष के बाद युद्ध इसी असहिष्णु मनोवृत्ति के परिचायक हैं। आज भी पश्चिम में अपने से इतर जातियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है; आज भी वहां के विद्वान यूरोप और अमेरिका को ही विश्व का केंद्र मानकर सारे संसार को उसके हितों के अनुसार नचाना चाहते हैं।

भारत में उसके विपरीत बहुत पहले ही सहिष्णुता की भावना का उदय हो चुका था। दो हजार मील लंबे और दो हजार मील चौड़े भारत की विविध रूपा प्रकृति के अंतर के सत्य का साक्षात्कार कराया। हमने विविधता में एकता की अनुभूति को और उसके परिणामस्वरूप सहिष्णुता की भावना को जन्म दिया। फलतः ज्ञान, कर्म और भाव तीनों ही क्षेत्रों में हमने अपनी सहिष्णुता की मनोवृत्ति का परिचय दिया है। 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' का आदर्श समक्ष रखकर ज्ञान के क्षेत्र में निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादन करके कर्म के क्षेत्र में तथा एक ही ब्रह्म के विविध रूप भिन्न देवताओं को मानकर भक्ति के द्वारा भाव के क्षेत्र में सहिष्णुता की भावना का विकास किया है। सहिष्णुता हमारे जीवन का अंग बन गई है।

आज पश्चिम का जीवन और उसका इतिहास ही प्रमुखतया अपने सम्मुख होने के कारण हमको अपनी सहिष्णुता की सहज प्रवृत्ति पर अभिमान होने लगा है। इतना ही नहीं, सहिष्णुता की भावना पर इतना जोर दिया जाने लगा है कि जीवन की दूसरी आवश्यक प्रवृत्ति अर्थात् जयिष्णु प्रवृत्ति की ओर हमारा दुर्लक्ष्य हो गया है। फलतः सहिष्णुता का अर्थ हो गया है, महत्वाकांक्षा से हीन, दुनिया को हर जाति के सामने झुकते जाना, अपने स्वत्व एवं जीवन को बिलकुल धूल में मिला देना। युद्ध चाहे वह आत्मरक्षार्थ ही क्यों न हो हमारे लिए पाप कार्य हो गया है। सिद्धांत के ऊपर इतना आग्रह हो गया है कि हम को भी चिंता नहीं कर रहे हैं।

> आदर्शवादी व्यक्तियों ने ही सब प्रकार की कठिनाइयां झेलकर भी संसार को आगे बढ़ाया है। जिनके जीवन में अपने आदर्शों को विजयी बनाने की महत्त्वाकांक्षा है, वे ही संसार के निराशामय वातावरण से ऊपर उठकर कुछ कर पाते हैं तथा दूसरों के लिए प्रकाश पुंज बनाकर मार्गदर्शक हो जाते हैं।

वास्तव में सहिष्णुता के समान ही जयिष्णुता का सिद्धांत भी आवश्यक है। यदि यह कहा जाए कि जयिष्णुता अधिक आवश्यक है तो अनुचित नहीं होगा। बिना जयिष्णुता की भावना के कोई समाज न तो जीवित ही रह सकता है और न वह अपने जीवन का विकास ही कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अथवा समाज केवल श्वासोच्छवास के लिए जीवित नहीं रहता, अपितु वह किसी आदर्श के लिए जिंदा रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस आदर्श की रक्षा के लिए अपने जीवन की परिसमाप्ति भी कर देता है। आदर्शवादी व्यक्तियों ने ही सब प्रकार की कठिनाइयां झेलकर भी संसार को आगे बढ़ाया है। जिनके जीवन में अपने आदर्शों को विजयी बनाने की महत्त्वाकांक्षा

है, वे ही संसार के निराशामय वातावरण से ऊपर उठकर कुछ कर पाते हैं तथा दूसरों के लिए प्रकाश पुंज बनाकर मार्गदर्शक हो जाते हैं। दुनिया के नए-नए देशों की खोज करनेवाले, प्रकृति के गुह्यतम सिद्धांतों को ढूंढ़ निकालनेवाले, ब्रह्म और जीवन के अभेद का साक्षात्कार करनेवाले, दुःखी मानवों को शांति और सत्य का उपदेश देने वाले, सबके सब अपने जीवन में एक महत्त्वाकांक्षा लेकर आए और उसे प्राप्त करने के निमित्त ही जीवन भर प्रयत्न करते रहे।

भारतवर्ष ने इस विजिगीषु वृत्ति का महत्त्व सदा ही समझा है और इसलिए विजयादशमी के त्योहारों की योजना की गई है। विजयादशमी हमारी विजयों का स्मारक तथा भावी विजयों का प्रेरक है। यह दिन हमको प्रतिवर्ष यादगार दिलाने आता है कि हमें दुनिया में विजय करनी है। हम पराजय के लिए अथवा उदासीन बनकर केवल 'अहार निद्रा भय मैथुनच्चु' तक ही अपने जीवन को सीमित करने के लिए नहीं, अपितु विलय के लिए पैदा हुए हैं।

विजय के लिए सीमोल्लंघन आवश्यक है। आज हमने अपने जीवन की सीमाएं बना रखी हैं। स्वार्थ और अज्ञान के संकुचित दायरे में हमने कूपमंडूक के समान अपने जीवन को सीमित कर दिया है। हमें अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी, जो इन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकता वह विजय भी नहीं प्राप्त कर सकता। सीमोल्लंघन और विजय केवल सेना और शास्त्रास्त्रों से सज होकर शत्रु के राज्य में कूच करके परास्त करने से ही नहीं होती, अपितु विचारों और भावनाओं के जगत् में भी यह विजय प्राप्त की जा सकती है। इस जगत् में भी हमारे अनेक शत्रु हैं जिनको पराजित करके हम अपनी विजय मना सकते हैं।

दुर्गा, रघु, राम और सिद्धार्थ के जीवन की घटनाएं विजयादशमी के साथ संबंद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक ने विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नता होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति की एकता स्पष्ट है। अतः हमारे जीवन में उनकी सी एकध्येयनिष्ठा तथा अपने जीवन से बाहर निकालकर आदर्श को प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा रही तो हम भी जीवन में विजय प्राप्त कर सकेंगे तथा सच्चे अर्थों में विजयादशमी मना सकेंगे। ■

मां विमलांबा प्रतिष्ठा महोत्सव

'हमारा देश एक जियो-पॉलिटिकल देश नहीं बल्कि एक जियो-कल्चरल राष्ट्र है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 20 जनवरी को पुरी (उड़ीसा) में मां विमलांबा प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और इस अवसर पर आयोजित जन-सभा को संबोधित किया।

गोवर्धन मठ, पुरी पीठाधीश पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब-जब मैंने पूज्यपाद से मिलने का समय मांगा, हर बार उन्होंने समय दिया, बड़े स्नेह से मेरा मार्गदर्शन किया और सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने कहा कि यह महाप्रभु जगन्नाथ का निवास तो है ही, साथ ही विश्व भर के हिन्दुओं के लिए एवं सनातन धर्मावलम्बियों के लिए अन्य कारणों से भी यह आस्था, विश्वास और श्रद्धा का केंद्र भी है क्योंकि यहां गोवर्धन पीठ है जहां से भगवान् आदिशंकर ने वेदों के संरक्षण व संवर्द्धन की शुरुआत की थी।

श्री शाह ने कहा कि पूज्यपाद आज जिस परम्परा के संरक्षण व संवर्धन का निर्वहन कर रहे हैं, उस परम्परा की शुरुआत जब लगभग 2500 वर्ष पहले हुई थी, तब हर तरफ सनातन धर्म पर संकट के बादल छाये हुए थे, सनातन धर्म के भविष्य को लेकर साधु-संत चिंतित थे, तब एक बालक ने आगे आकर आश्चर्यचकित कर देने वाली अपनी ज्ञान एवं मेधा के सहारे सनातन धर्म का पुनरुद्धार करते हुए इसे फिर से प्रतिष्ठित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि पूज्य श्री उसी महान परम्परा के वाहक हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि आश्चर्य होता है कि अल्पायु में ही एक व्यक्ति इतने सारे काम कैसे कर सकता है, तब मन यह मानने को लालायित हो उठता है कि यह बालक मानव नहीं बल्कि साक्षात भगवान् शंकर का अवतार है। उन्होंने कहा कि भगवान् आदिशंकर ने इतने अल्पकाल में ही चार पीठों को प्रतिस्थापित किया, चार-धाम को पुनः प्रतिष्ठित किया, 52 शक्तिपीठों की व्याख्या की, उनका पुनरुद्धार किया, ज्योतिर्लिंगों का भी पुनरुद्धार किया, संन्यास व्यवस्था को 10 अखाड़ों में बांटकर एक वैज्ञानिक व्यवस्था देने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आचार्य शंकर ने अनेक प्रकार के भाष्यों की भी रचना की, चाहे वह श्रीमद्भागवद्गीता पर लिखा गया भाष्य हो या उपनिषद् पर लिखा गया भाष्य हो अथवा ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया भाष्य हो।

श्री शाह ने कहा कि इतने वर्षों की महान परम्परा का निर्वहन कर रहे जगतगुरु श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के चरणों में जब-जब मुझे बैठने का मौक़ा मिला, उन्होंने कभी पीठ अथवा अपनी संस्थाओं के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा तो देश की व्यवस्था के लिए कहा, देश के सुधार के लिए कहा और सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए कहा, यही विचार सनातन धर्म को दुनिया में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित करता है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज मां विमला का भव्य मंदिर पूज्यपाद के मार्गदर्शन में बना है, प्राण-प्रतिष्ठा भी उन्हीं के माध्यम से हुई है, जिस तरह से महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर सबको शांति देता है, इसी तरह से माँ विमला का यह भव्य मंदिर सदियों तक श्रद्धालुओं को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए उन्होंने श्री गजपति जी का हृदय से आभार प्रकट किया। ■

दीनदयालजी की याद में

| ओ. राजगोपाल |

पं. दीनदयाल उपाध्याय मेरे राजनैतिक गुरू थे। वही मुझे वर्ष 1961 में भारतीय जनसंघ में लेकर आए। उस समय मैं पालघाट, केरल में वकालत कर रहा था, जब परमेश्वरनजी (तत्कालीन प्रदेश जनसंघ के संगठन मंत्री और अब विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं) ने मुझे उनसे भेंट कराई। दीनदयालजी शरीर से पतले दुबले थे, उनका व्यक्तित्व कोई प्रभावशाली नहीं था। वे बड़े सरल थे, परन्तु वे तीव्र बुद्धि के थे, उनके तर्क अकाट्य रहते थे। फिर भी वे यथार्थवादी थे। मैं उनके इस राजनैतिक विचारों से बहुत आकर्षित हुआ था कि भारतीय राजनीति एक धार्मिक कार्य है, जबकि पश्चिमी देशों में इसे व्यवसाय माना जाता है। 1950 के दशक में हम इस इस बात से नाराज थे कि नेहरू जैसे कांग्रेस के महान नेताओं ने भी गांधीवादी विचारों के साथ विश्वासघात किया और अवाडी अधिवेशन में 'समाजवादी आदर्श' को मानते हुए कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी विचारधारा का विकल्प अपनाया। उस समय स्टीफन स्पेंडर जैसे विख्यात चिंतक, जो मूलतः समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, से भी उनका मोह भंग टूट गया था, क्योंकि इस विचारधारा की हिमायत कर रहे थे, उन्हें सोवियत रूस में सत्ता मिली और यह सिद्ध हो गया कि वे आर्थिक मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, बल्कि इस विचारधारा को अपनाने से तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का ही हनन होगा। उनकी विख्यात पुस्तक 'दि गोड देट फेल्ड' ने बहुत से लोगों की आंखें खोल दीं।

समाजवादी चिंतकों का एक और दोष भी हमारे सामने प्रगट हो गया जब हमने पूज्य स्वामी चिन्मयानंद तथा गुरूजी जैसे अपने प्राचीन विद्वानों के भाषणों को सुना, जिसमें उन्होंने हमें जीवन के लौकिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर देने को कहा। समाजवादी मानव के आध्यात्मिक पक्ष को मानते ही न थे। बल्कि उनका मानना था कि अध्यात्म तो देश की भौतिक प्रगति के लिए रोड़ा है। इस प्रकार नेहरूवादी विचारकों ने व्यावहारिक रूप से गांधीवाद को त्याग दिया और समाजवाद के प्रशंसक बन गए।

यह वह समय था, जब मैं दीनदयालजी के सम्पर्क में आया, जिन्होंने एकात्म मानववाद के अपने विख्यात भाषण में 'धर्म राज्य' की विचारधारा को प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव और समाज के समग्र विकास पर बल दिया। उन्होंने धर्म, अर्थ और मोक्ष के महत्व को समझाया। मैं उनकी बातों से और अधिक प्रभावित हुआ और महसूस किया कि भारत के लिए न तो पूंजीवाद और न ही समाजवाद उपयुक्त है, बल्कि एकात्म मानववाद और धर्म राज्य की विचारधारा ही महत्वपूर्ण है। मैं जनसंघ में शामिल हो गया और मुझे दीनदयालजी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला।

दीनदयालजी ने व्यापक रूप से केरल का दौरा किया। वे सभी जिलों में गए। उन दिनों समाजवाद का बोलबाला था। केरल में कम्युनिस्टों के पास सत्ता थी। दीनदयालजी की संगठनात्मक क्षमता बड़ी प्रभावशाली थी। वे केरल को बहुत पसंद करते थे। वे आदि शंकराचार्य के बड़े भारी प्रशंसक थे और उन्होंने शंकराचार्य के जन्मस्थल कलाडी में शंकराचार्य मन्दिर में पूजा–अर्चना की।

यद्यपि केरल में जनसंघ का काम अत्यंत नगण्य था, फिर भी दीनदयालजी ने जनसंघ का 14वां वार्षिक सम्मेलन केरल में रखने पर जोर दिया। उन्होंने हमें हर तरह की सहायता और मार्गदर्शन दिया। मैं तब स्वागत समिति का सचिव था। 28, 29 और 30 दिसम्बर 1967 को सम्पन्न हुए इस अधिवेशन में भी दीनदयालजी की इच्छा न रहने पर भी उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 41वें दिन उन्हें मुगलसराय रेलवे स्टेशन यार्ड में हत्या होने के कारण मृत अवस्था में पाया गया। मुझे उनकी हत्या का समाचार सुनकर बेहद दुख हुआ। उनकी शोक सभा में मैंने अपनी वकालत छोड़ने का निर्णय लेने की घोषणा की और कहा कि मैं पूरी तरह से दीनदयालजी के सपनों को साकार करने के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन के आदर्शों को अपना कर अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी कामना है कि उनका जीवन और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। ■

दीनदयालजी मानव और समाज के समग्र विकास पर बल दिया। उन्होंने धर्म, अर्थ और मोक्ष के महत्व को समझाया। मैं उनकी बातों से और अधिक प्रभावित हुआ और महसूस किया कि भारत के लिए न तो पूंजीवाद और न ही समाजवाद उपयुक्त है, बल्कि एकात्म मानववाद और धर्म राज्य की विचारधारा ही महत्वपूर्ण है।

(लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं)

मुस्लिम उलेमाओं–बुद्धिजीवियों–शिक्षाविदों की प्रधानमंत्री से मुलाकात

भारतीय युवाओं ने कट्टरता का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है: नरेन्द्र मोदी

मुस्लिम उलेमाओं, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधिमंडल और गणमान्य व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से 19 जनवरी को मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गये कदमों के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल ने भारत के हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सऊदी सरकार के निर्णय की सराहना की और इस मामले को सफलतापूर्वक उठाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर से भ्रष्टाचार और काला धन के विरूद्ध प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गये अभियान का जोरदार समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई से सर्वाधिक अल्पसंख्यकों सहित गरीब व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

प्रतिनिधिमंडल ने विश्व भर के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गये प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि आज विश्व के प्रत्येक कोने में रहने वाला प्रत्येक भारतीय गर्व का अनुभव कर रहा है।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने स्वच्छ भारत की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों के लिए भी उनकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं ने कट्टरता का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है, जिसने विश्व के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जनता के दीर्घकालिक, साझा विरासत को इसका श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विरासत को आगे बढ़ाना हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपरा और इसका सामाजिक ताना-बाना कभी भी आतंकवादियों अथवा उनके प्रायोजकों के कुत्सित मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया, जो लाभदायक रोजगार तथा गरीबी से उत्थान का माध्यम है। भारत के हज यात्रियों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित सऊदी अरब सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश में भारतीय मुसलमानों की सकारात्मक छवि है।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में इमाम उमर अहमद इलियासी (अखिल भारतीय मस्जिद इमाम संगठन के भारत में मुख्य इमाम), ले. जन. (सेवानिवृत्त) जमीरूद्दीन शाह (कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), एम. वाई. इकबाल (पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय), तलत अहमद (कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया), और शाहिद शिद्दिकी (उर्दू पत्रकार) शामिल थे। इस अवसर पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री श्री एम. जे. अकबर भी उपस्थित थे। ■

अभूतपूर्व बदलाव लानेवाली कृषि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन

सरकार ने किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु सामान्य ई-मार्केट प्लेटफार्म की शुरुआत की है। 585 नियंत्रित मंडियों को जोड़ने के उद्देश्य के साथ स्थापित इस ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर 250 मंडियों को जोड़ा जा चुका है।

| पुरुषोत्तम रूपाला |

मई, 2014 में अपना कार्यभार संभालने के उपरांत वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा समुचित एवं पर्याप्त बाजार सुधारों के साथ कृषि उत्पादकता व वित्तीय लाभ को बढ़ाने और किसानों द्वारा महसूस किए जाने वाले दबावों में कमी लाने हेतु समर्थ प्रयास किए गए हैं। इन्हें अनिवार्य रूप से कृषि प्रभावशीलता और व्यावसायिक विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए भारत का पूर्वी क्षेत्र, जो कि कृषि क्षेत्र में एक बिना दोहन वाला क्षेत्र है। देश में दूसरी हरित क्रांति लाने की दिशा में कृषि में संस्थागत विकास और आपूर्ति में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों की खुशहाली और बेहतर रहन-सहन को हासिल करने की दिशा में, 30 महीनों के कार्यकाल में अनेक नए और अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा उत्पादकता (बेहतर निवेश, जोखिम प्रबंधन) लाभप्रद व्यावसायीकरण (विविधीकृत कृषि प्रणाली, बाजार सुधार) प्रतिस्पर्धा तथा गवर्नेंस (डी.बी.टी., भूमि सुधार) पर किसानों को शामिल करना प्रारंभ किया गया है।

मुख्य कार्य के रूप में किसान कल्याण करने हेतु जोखिम-प्रबंधन मूल्य उतार-चढ़ाव तथा मूल्य स्थिरीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना इस सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अनेक प्रमुख पहलों में पूरी तरह से समर्पित एक टीवी चैनल 'किसान चैनल' शामिल है, जिस पर कृषि के सभी पहलुओं पर मूल्यवान जानकारी प्रदान की जाती है।

सरकार ने किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु सामान्य ई-मार्केट प्लेटफार्म की शुरुआत की है। 585 नियंत्रित मंडियों को जोड़ने के उद्देश्य के साथ स्थापित इस ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर 250 मंडियों को जोड़ा जा चुका है।

भारत सरकार कृषि को नई गति देने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा देना, गुजरात में काजू की खेती को बढ़ावा देना, राजस्थान में जैतून की पैदावार बढ़ाना तथा पिस्ता की पैदावार बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) के तहत नाबार्ड निधि (NABARD Funds) को 21000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 41,000 करोड़ रुपए कर दिया है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की बढ़ी हुई दृश्यता (विजीबिलिटी) से कृषि पेशे के प्रति सम्मान बढ़ा है और कृषि व्यवसाय में लोगों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

यहां मैं सभी संबंधितों की जानकारी के लिए कृषि क्षेत्र में सरकार की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की प्रगति यात्रा रखना चाहूंगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFSY) को खरीफ 2016 से लागू किया गया। इस योजना को तत्कालीन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) के स्थान पर लागू किया गया था। तत्कालीन योजनाओं की तुलना में इसमें यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि देश भर में फसल/क्षेत्रों के लिए वास्तविक प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी को तर्कसंगत बनाया गया और खरीफ खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहनी फसलों के लिए सुनिश्चित राशि की 2%, रबी खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए 1.5% और खरीफ तथा रबी की वार्षिक व्यावसायिक/वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई।

फसल के दौरान विपरीत मौसम जैसे कि - बाढ़, सूखा अवधि गैर मौसमी वर्षा के मामले में संभावित उपज, सामान्य उपज से 50% कम रहने की स्थिति में संभावित दावों का 25% तक का तत्काल ऑन अकाउंट भुगतान किया जाएगा। फसलोपरांत नुकसान, स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, भू-स्खलन से क्षति का आकलन कर किसान भाईयों के क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए अब तक कुल 13,240 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पिछले खरीफ मौसम 2015 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 23 राज्यों के 309 लाख किसानों को शामिल किया गया था। खरीफ 2016 के दौरान कुल 377.46 लाख किसानों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें से 272.84 लाख किसान कर्जदार और 104.57 लाख किसान गैर कर्जदार हैं।

इस योजना में सभी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावा की गणना और भुगतान के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। किसानों की शिकायत निपटाने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे कॉल सेंटर और पोर्टल की व्यवस्था की गई है। यह योजना किसानों को जटिलताओं से मुक्त कर उनके लिए सभी फसली जोखिमों पर क्षतिपूर्ति का एक सरल प्रारूप प्रस्तुत करती है और देश के किसानों को लाभान्वित करने और जोखिम कवरेज की दृष्टि से अभूतपूर्व है।

मृदा स्वायल कार्ड योजना - हरित क्रांति के सूत्रपात के साथ ही भारत में उर्वरकों के प्रयोग में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में यूरिया के प्रयोग में अंधाधुंध बढ़ोतरी हुई है। यह एक प्रचलित मान्यता है कि भारतीय किसान यूरिया का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। मृदा एवं फसल की प्रवृत्ति तथा सिंचित बनाम बारानी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अधिक गहन विश्लेषण पर ध्यान दिया जा रहा है। अब मृदा स्वायल कार्ड योजना लागू की जा रही है, ताकि किसानों को उनके खेत के पोषक स्तर के बारे में जानकारी दी जा सके ताकि वे उर्वरकों का समुचित प्रयोग करने में समर्थ बन सकें। इस योजना के तहत मार्च, 2017 तक 14 करोड़ फार्म होल्डिंस (Farm Holdings) को शामिल किए जाने का लक्ष्य है। मृदा स्वायल एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए 368 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही अगले तीन वर्षों में मृदा एवं बीज परीक्षण सुविधाओं के साथ उर्वरक कम्पनियों के 2000 मॉडल रिटेल आउटलेट्स भी प्रदान किए जाएंगे।

कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें कृषि क्षेत्र की विद्यमान समस्याओं का निवारण, निरंतर उत्पादन बढ़ाने, कृषि को मजबूती प्रदान करने और किसानों को सहयोग देने की अपार क्षमता निहित है।

मार्च 2017 तक कुल 2.53 करोड़ मृदा नमूनों का संकलन करने के लक्ष्य के मुकाबले 17 जनवरी, 2017 तक 2.44 करोड़ मृदा नमूने संकलित किए गए हैं। इन मृदा नमूनों से करीब 14 करोड़ मृदा स्वायल कार्ड तैयार करने का लक्षित कार्य प्रगति पर है। पिछले दो वर्षों के दौरान 460 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। 460 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अलावा 4000 मिनी लैब भी राज्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रयोग आधारित उचित उर्वरकों के उपयोग से उपज लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि होना निश्चित है।

कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें कृषि क्षेत्र की विद्यमान समस्याओं का निवारण, निरंतर उत्पादन बढ़ाने, कृषि को मजबूती प्रदान करने और किसानों को सहयोग देने की अपार क्षमता निहित है। ■

(लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायत राज राज्यमंत्री हैं)

व्यापक, सर्वसमावेशी और भविष्योन्मुखी है हमारा संविधान

किसी देश का संविधान उसके राजनीतिक जीवन और व्यवस्था का वह आधारभूत सांचा–ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी व्यवस्था शासित होती है। किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधारविधि भी कहा जा सकता है, जो उसकी राज्यव्यवस्था के मूल आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को मूर्त करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी नैतिक तथा कानूनी वैध्यता के लिये जांचा जाता है। हम कह सकते हैं कि अपने आदर्श रूप में प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का प्रतिबिम्ब होता है।

| डॉ. शिव शक्ति बक्सी |

भारतीय संविधान पर बराबर बहस होती रही है और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की यह पहचान है कि वह समय–समय पर अपने आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण करता रहे। भारतीय संविधान की व्यापकता, सर्वसमावेशी एवं भविष्योन्मुखी चरित्र पर शायद ही किसी को शंका रही होगी, परन्तु इसके विभिन्न पहलुओं पर व्याख्या को लेकर वैचारिक द्वन्द्व होते रहे हैं।

किसी देश का संविधान उसके राजनीतिक जीवन और व्यवस्था का वह आधारभूत सांचा–ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी व्यवस्था शासित होती है। किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधारविधि भी कहा जा सकता है, जो उसकी राज्यव्यवस्था के मूल आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को मूर्त करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी नैतिक तथा कानूनी वैध्यता के लिये जांचा जाता है। हम कह सकते हैं कि अपने आदर्श रूप में प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का प्रतिबिम्ब होता है।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि संविधान के नियमों के अनुसार शासन–संचालन मात्र ही संविधानवाद है। एक निरंकुश तानाशाह या वैचारिक अंधत्व से चालित नेतृत्व भी इच्छानुसार संविधान बनाकर जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की अवहेलना करता हुआ उन पर बलपूर्वक संविधान लागू कर सकता है। चूंकि ऐसे संविधान से जनता के आदर्शों, मूल्यों और संस्कृति और परम्परा का समावेश नहीं होता। अतः उस शासन व्यवस्था को संविधानवाद के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। अतः संवैधानिक शासन का आदर्श, संविधान का अर्थ, लिखित मूर्त संविधान से कुछ अधिक है। आदर्श संविधान वही

है, जिसमें मनुष्य की संस्कृति, मान्यताओं, आस्थाओं और मूल्यों की व्यवहार में उपलब्धि संभव हो सके, से है। इन्हीं मूल कसौटियों पर हम भारतीय संविधान की सार्थकता और प्रासंगिकता को जांच सकते हैं। संविधान को एक स्थिर घोषणापत्र मात्र लेना ठीक नहीं होगा, उसे देश की संस्कृति और वैश्विक तथा समसामयिक चुनौतियों में दबाव के तहत निरंतर पल्लवनशील होना चाहिए।

किसी भी संविधान की उद्देशिका (preamble) की भांति भारतीय संविधान की उद्देशिका से आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित हो तथा जिन तथ्यों उद्देश्यों को प्राप्ति का प्रयास करने के लिये संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उसमें समावेश हो। हमारे संविधान की उद्देशिका में जिस रूप में उसे संविधान सभा ने पास किया था, कहा गया है कि ''हम भारत के लोग'' भारत को एक ''प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य'' बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने और उनमें बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प करते हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका में निःसंदेह बहुत ही भव्य और उदात्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचारधारा या वाद–विशेष से जुड़ा हो या किसी आर्थिक सिद्धांत द्वारा सीमित हो। इसलिए वे उसमें, अन्य बातों के साथ, समाजवाद के किसी उल्लेख को सम्मिलित करने के लिये सहमत नहीं हुए थे। नवंबर 1948 में बिहार से सदस्य केटी शाह का प्रस्ताव कि संविधान की धारा 1, खंड 1 में 'पंथनिरपेक्ष, संघ एवं समाजवाद' जोड़ा जाए से बाबा साहेब अंबेडकर सहमत नहीं थे। जहां एक ओर उन्होंने पंथनिरपेक्षता को एक सार्वभौमिक मूल्य मानते हुए इसका संविधान में अलग से उल्लेख आवश्यक नहीं माना। समाजवाद के प्रश्न पर उनका मत था कि समय–समय पर आवश्यकतानुसार आने वाली पीढ़ियां कैसे स्वयं को संगठित करना चाहती हैं, यह उन पर छोड़ देना चाहिए। संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा हमारे गणराज्य की विशेषता दर्शाने के लिये 'समाजवाद' शब्द का समावेश दिया गया, पर हम जानते हैं कि 'समाजवाद' की परिभाषा करना कठिन है। विभिन्न लोग इसका भिन्न–भिन्न अर्थ लगाते हैं और इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है।

व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक शांति के लिये एक प्रभावी साधन बने। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निदेशक तत्व देश के शासन के मूलाधार है और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किंतु विडम्बना है कि निदेशक तत्वों से ऐसे कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलते, जिनका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति उसका उपचार कर सके और न यह विधायिका को कोई अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। ये समादेश न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गये थे और इन्हें जानबूझकर ऐसे शब्दों में व्यक्त किया गया था, जिनसे विधायिका को क्रम, समय और पूरा करने की रीति का निर्णय करने की कुछ हद तक छूट रहे, क्योंकि उनका कार्यान्वयन अनेक सूक्ष्म तत्वों पर निर्भर करता है।

संविधान सभा में बोलते हुए डा. अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि वे केवल पूजनीय आदर्श बनकर रह जाएं। उन्होंने कहा था कि ''संविधान सभा का आशय यह है कि भविष्य में विधायिका तथा कार्यपालिका, दोनों इस भाग में अधिनियमित इन तत्वों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति न जताएं, बल्कि इन्हें कार्यपालिका तथा विधायिका के उन सभी कार्यों का आधार बना दिया जाए जो इसके बाद देश के शासन के मामले में किये जाएं। निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 48 कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को यह आदेश देता है कि ''कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो–वध का प्रतिषेध हो। अनुच्छेद 49 समूचे देश के लिये समान नागरिक संहिता को रेखांकित करता है। 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता का जोरदार समर्थन करते हुए कहा था कि यदि धर्म को कानून बनाने के आड़े आने दिया जाएगा तब इस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन आज वही हो रहा है जिसकी कल्पना शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की होगी।

किसी भी संविधान की उद्देशिका (preamble) की भांति भारतीय संविधान की उद्देशिका से आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित हो तथा जिन तथ्यों उद्देश्यों को प्राप्ति का प्रयास करने के लिये संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उसमें समावेश हो।

इस बात को समझा जाना चाहिए कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व सभी एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है और उन्हें एक–दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। हमारे देश के वामपंथी और प्रतिक्रियावादी तत्त्व उद्देशिका और मूल अधिकारों के प्रति तो अतिवादी रूख रखते हैं पर नीति निदेशक तत्वों के प्रति नकारात्मक और प्रतिक्रियावादी दृष्टि रखते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यापक, सर्वसमावेशी एवं भविष्योन्मुखी संविधान हमें सौंपा है। संविधान की भविष्य की दिशा के लिए भी उन्होंने दिशा स्पष्ट की है और समाज के उत्तरोत्तर विकास के साथ देश की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकता के सामंजस्य की संभावनाएं इसमें है। 'उदारवाद' का चोला ओढ़े विभिन्न विचार के लोग आज संविधान के इस विराट स्वरूप में असहज महसूस करते हैं। किसी भी संविधान प्रदत्त सकारात्मक परिवर्तन के लिए यह 'उदारवादी' तबका बड़ी ढिठाई से 'अनुदार' बन जाता है। इसका परिणाम अल्पसंख्यकवाद के नाम पर धर्मांधता के रूप में सामने आ रहा है, जिससे अल्पसंख्यकों के बीच सकारात्मक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले भी अकेले पड़ जाते हैं। अब समय आ गया है कि संविधान के महान सिद्धांतों की सकरात्मक व्याख्या हो और 'उदारवादी' तबका सही में उदारवाद की ओर प्रवृत्त हों और देश सकरात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ सके। ■

स्वच्छ भारत मिशनः आगे की राह

गांधी जी के इन्हीं साफ-सफाई से संबंधित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को "स्वच्छ भारत मिशन " की शुरूआत करने के लिए चुना। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत के प्रति दृष्टिकोण और विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के "दुर्गंध-मुक्त स्वराज " के प्रति ही बढ़ा एक और कदम है।

| उमाकांत लखेड़ा |

महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए वर्षों में दो घटनाएं साफ तौर पर प्रभावित करती हैं। पहली, वह नस्लीय भेदभाव जिसका उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सामना करना पड़ा, जब उन्हें एक असभ्य यूरोपियन नागरिक द्वारा उनके सवालों से तंग आकर पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और दूसरी घटना साफ-सफाई और स्वच्छता से संबंधित है। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के गरीब काले पुरुषों को दूसरों के शौचालय की सफाई और उनके मलमूत्र को सिर पर बाल्टी में ले जाते देखा तो उन्हें आंतरिक दुःख हुआ। इस छोटी सी घटना ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इसी दिन गांधी जी ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने शौचालय की सफाई खुद करेंगे। उन्होंने अपने व्रत को मन में दोहराते हुए प्रतिज्ञा की, "यदि हम अपने शरीर को खुद साफ नहीं रख सकते तो हमें अपने स्वराज से बेईमानी एक दुर्गंध की तरह होगा।"

गांधी जी के इन्हीं साफ-सफाई से संबंधित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को "स्वच्छ भारत मिशन " की शुरूआत करने के लिए चुना। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत के प्रति दृष्टिकोण और विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के "दुर्गंध-मुक्त स्वराज " के प्रति ही बढ़ा एक और कदम है।

यह मिशन, जो केंद्र सरकार के विशालतम स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा है, को शहरी तथा ग्रामीण घटकों में विभाजित किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है।

यह मिशन, जो केंद्र सरकार के विशालतम स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा है, को शहरी तथा ग्रामीण घटकों में विभाजित किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की कमान शहरी विकास मंत्रालय को दी गई है और 4041 वैधानिक कस्बों में रहने वाले 377 लाख व्यक्तियों तक स्वच्छता हेतु घर में शौचालय की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। इसमें पांच वर्षों में करीब 62009 करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है जिसमें केन्द्र सरकार 14623 करोड़ रूपये की राशि सहायता के तौर पर उपलब्ध करायेगी। इस मिशन के अंतर्गत 1.04 करोड़ घरों को लाना है जिसके तहत 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना तथा सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा मुहैया करना है।

इस मिशन के 6 प्रमुख घटक हैं-

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय;
2. सामुदायिक शौचालय;
3. सार्वजनिक शौचालय;
4. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;
5. सूचना और शिक्षित संचार (आईईसी) और सार्वजनिक जागरूकता;
6. क्षमता निर्माण

शहरी मिशन के तहत खुले में शौच को समाप्त करना; अस्वास्थ्यकर शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करना; और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा का विकास करना है। इस मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच के हानिकारक प्रभावों, बिखरे कचरे से पर्यावरण को होने वाले खतरों आदि के बारे में शिक्षित कर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में शहरी स्थानीय निकायों का बेहतरीन तरीके

से इस्तेमाल किया जा सकता है तथा साथ ही इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी ली जा सकती है।

ग्रामीण मिशन, जिसे स्वच्छ भारत ग्रामीण के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से ग्राम पंचायतों को मुक्त करना है। इस मिशन की सफलता के लिए गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी से क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना भी है।

गांव के स्कूलों में गन्दगी और मैली की स्थिति को देखते हुए, इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के साथ शौचालयों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी शौचालय और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन इस मिशन की प्रमुख विषय-वस्तु है। नोडल एजेंसियां ग्राम पंचायत और घरेलू स्तर पर शौचालय के निर्माण और उपयोग की निगरानी करेंगी। ग्रामीण मिशन के तहत 134000 करोड़ रूपये की लागत से 11.11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधान के तहत, बीपीएल और एपीएल वर्ग के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक शौचालय के लिए क्रमशः 9000 रुपये और 3000 रुपये का प्रोत्साहन -निर्माण और उपयोग के बाद- दिया जाता है। उत्तर-पूर्व के राज्यों, जम्मू-कश्मीर तथा विशेष श्रेणी के क्षेत्रों के लिए यह प्रोत्साहन राशि क्रमशः 10800 रुपये और 1200 रुपये है।

कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है, परिणाम उम्मीद से अधिक हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014-15 में 5854987 शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि लक्ष्य 50 लाख शौचालयों का ही था। इसमें लक्ष्य के 117 प्रतिशत तक सफलता हासिल हुई है। 2015-16 में 127.41 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है जो लक्ष्य 120 लाख से ज्यादा है। 2016-17 में लक्ष्य 1.5 करोड़ रखा गया और इसमें 1 अगस्त 2016 तक 3319451 शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा बाकी के लिए भी तेजी से काम चल रहा है।

ग्रामीण मिशन के तहत 1 अक्टूबर 2014 से 1 अगस्त 2016 तक 210.09 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसी अवधि में स्वच्छता का दायरा 42.05 प्रतिशत से बढ़कर 53.60 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

ग्रामीण मिशन के तहत 1 अक्टूबर 2014 से 1 अगस्त 2016 तक 210.09 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसी अवधि में स्वच्छता का दायरा 42.05 प्रतिशत से बढ़कर 53.60 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

अंत में, स्वच्छता की कार्यप्रणाली में क्या व्यवहारिक परिवर्तन हुआ है यही मायने रखता है। यह जिलाधिकारियों, सीईओ, जिला पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्षों के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल होता है। इस सफाई अभियान से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यशालाओं द्वारा अलग-अलग राज्यों में कार्य किया जा रहा है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए मजबूती से इसके पीछे खड़े हैं। केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय उसके प्रतिनिधियों के राज्यों का दौरा करने और समन्वय बैठकों में भाग लेने से बढ़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन सही रास्ते पर अग्रसर है। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत को जोड़ेगा डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य 127 करोड़ भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ना है। इन सबको कम लागत के डाटा प्लान और स्मार्ट फोन (या अन्य उपकरण) के जरिये इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ताकि एक परोक्ष राष्ट्र का निर्माण हो सके। यह मिशन ई गवर्नेंस के बिना किसी मध्यस्थ और निचले स्तर के भ्रष्टाचार के हर भारतीय की सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक सीधे पहुंच बनाएगा। हर भारतीय चाहे उसकी हैसियत कुछ भी क्यों न हो, उसे समान स्तर की सेवाएं उपलब्ध होंगी।

| मोहनदास पई |

प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों को जोड़ने और उनके सशक्तीकरण के लिए डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण रखा है। सही मायने में यह परिवर्तनकारी सपना है, जिससे भारत का कायापलट हो जाएगा और डिजिटल सोसाइटी के निर्माण से बाधाएं और दूरियां खत्म हो जाएंगी। यह हमें एकजुट करेगा और सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा और ऐसी पीढ़ी का निर्माण करेगा, जो, कि हर नजरिये से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। यह इसलिए अहम है, क्योंकि हाल ही में 86 फीसदी करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया है और व्यापक रूप में डिजिटल बैंकिंग का अभियान छेड़ा गया है।

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य 127 करोड़ भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ना है। इन सबको कम लागत के डाटा प्लान और स्मार्ट फोन (या अन्य उपकरण) के जरिये इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ताकि एक परोक्ष राष्ट्र का निर्माण हो सके। यह मिशन ई गवर्नेंस के बिना किसी मध्यस्थ और निचले स्तर के भ्रष्टाचार के हर भारतीय की सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक सीधे पहुंच बनाएगा। हर भारतीय चाहे उसकी हैसियत कुछ भी क्यों न हो, उसे समान स्तर की सेवाएं उपलब्ध होंगी। अधिकांश सरकारी सेवाएं और योजनाएं इलेक्ट्रानिक रूप में पूरे भारत में उपलब्ध होंगी, जिनसे जाहिर है पारदर्शिता के साथ डाटा का विशाल संग्रह बन जाएगा। इससे लोगों की मुश्किलें और शिकायतें समयबद्ध तरीके से दूर हो सकेंगी।

'इंडिया स्टेक' एक एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस), जिसके जरिये हर भारतीय को मोबाइल फोन पर हर तरह की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिनसे वह बैंकिंग संबंधी सेवाएं बहुत ही कम लागत पर हासिल कर सकेगा। इसके जरिये खाते संबंधी जानकारी हासिल की जा सकती है, भुगतान किया जा सकता है और उसके खाते में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण हो सकता है। अपने घर में बैठकर ही जीवन बीमा, मेडिकल बीमा और अन्य तरह के निवेश किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रानिक लेन-देन बढ़ने से कर अपवंचन कम होगा और कर संग्रह बढ़ेगा। साथ ही सरकारी सेवाओं के संबंधित व्यक्ति तक प्रसारण में भ्रष्टाचार और अन्य कारणों से होने वाला नुकसान कम होगा।

हर भारतीय के पास उसके स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध होगा और वह देश के किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क कर इलाज करवा सकेगा। यहां तक कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेहतर इलाज हासिल कर सकेंगे और उन तक आपात स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी।

दस वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे मल्टीमीडिया एजुकेशन कंटेंट से युक्त टेबलेट के जरिये अपनी पसंद की भाषा में अपना ज्ञान संवर्धित कर सकेंगे। वह फोर-जी और वाई-फाई कनेक्शन के जरिये श्रेष्ठ शिक्षकों के लेक्चर, क्विज, डाक्यूमेंटरी हासिल कर सकेंगे। इससे निश्चय ही स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण करने का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा और वे कहीं अधिक सुगमता और अपनी सुविधा से शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इस तरह उनके लिए विश्व की शिक्षा संबंधी सर्वश्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध कराई जा सकेगी। पाठ्य पुस्तकें भी ई रूप में उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे इन्हें पुस्तक रूप में खरीदने पर होने वाला खर्च खत्म/ कम हो जाएगा।

भारत पारंपरिक दस्तकारों और किसानों की भूमि है। स्वरोजगार से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, फिर वह दस्तकार हो, किसान हो या फिर सेवा प्रदाता, उसका अपना एक वेब पेज होगा, जिसमें पेमेंट गेट-

वे होगा और वह किसी भी उपभोक्ता के साथ सीधे लेन-देन कर सकेगा। इससे उत्पादक और उपभोक्ता सीधे आपस में जुड़ सकेंगे और बिचौलियों के कारण होने वाला नुकसान कम हो जाएगा। इससे स्वरोजगार करने वाला एक नया वर्ग तैयार हो जाएगा, जिसकी बाजार तक सीधे पहुंच होगी। ई-कॉमर्स के जरिये हर भारतीय की वस्तुओं और सेवा तक सीधी पहुंच हो जाएगी। यही नहीं, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में आसानी से पता किया जा सकेगा।

डिजिटल इंडिया के असर से मनोरंजन उद्योग और लोगों की मनोरंजन से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो सकेगी। विभिन्न भाषाओं की फिल्में, संगीत और अन्य तरह की सामग्री के उनके पास ढेरों विकल्प मौजूद होंगे। सही मायने में फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर के श्रोता या दर्शक मिल सकेंगे। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की आर्काइव बहुत समृद्ध है, उनकी सामग्री मुफ्त में उपलब्ध होगी। हर तरह की ऐसी किताबें, पांडुलिपियां और अन्य दस्तावेज को कॉपीराइट से मुक्त हो चुके हों, मुफ्त में इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हो सकेंगे। यहां तक कि दुनियाभर की बेहतर सामग्री भी भारतीयों के लिए सहजता से उपलब्ध हो सकेगी।

> पहुंच बढ़ने से गरीबों और वंचितों का सशक्तीकरण होगा। बेहतर संवाद, विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान और सूचनाओं और जानकारियों की उपलब्धता से लोकतंत्र मजबूत होगा।

विभिन्न ऐप के जरिये हर भारतीय देश के किसी भी हिस्से में या विदेश में रह रहे अपने परिजनों और मित्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संपर्क कर सकेगा। खासतौर से ऐसे बुजुर्ग पालकों का एकाकीपन दूर हो सकेगा, जिनके बच्चे उनसे दूर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सहित अन्य नेता सीधे लोगों से जुड़ सकेंगे और लोग भी अपने विचार और समस्याएं सीधे उन तक पहुंचा सकेंगे।

पहुंच बढ़ने से गरीबों और वंचितों का सशक्तीकरण होगा। बेहतर संवाद, विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान और सूचनाओं और जानकारियों की उपलब्धता से लोकतंत्र मजबूत होगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर तरह के वंचित लोगों की, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले और महिलाएं शामिल हैं, प्रधानमंत्री बीपीएल योजना या एलपीजी योजना की तरह स्मार्ट फोन मिल सकें।

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस कार्य को अगले दो वर्ष में पूरा किए जाने का भरोसा है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कम लागत के 4-जी डाटा प्लान की उपलब्धता आसान हुई है। हम डिजिटल इंडिया के जरिये एक परोक्ष एकजुट भारत का निर्माण कर सकते हैं। ■

साभार- अमर उजाला

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 82,708 करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति

18 जनवरी की दी गई मंजूरी के साथ पिछले साल जून में लांच की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित में कुल स्वीकृत मकानों का आंकड़ा अब 15,48,846 हो गया है। इन मकानों के लिए 21,125.36 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ कुल मिलाकर 82,708 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई है।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 18 जनवरी को 1,942.24 करोड़ रुपये के निवेश और 785.04 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस के लिए 52,336 और मकानों को मंजूरी दी। वहीं, पश्चिम बंगाल के खाते में 861.62 करोड़ रुपये के निवेश एवं 319.27 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 21,285 और मकान आये। साथ ही, मंत्रालय ने 152.46 करोड़ रुपये के निवेश एवं 76.23 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ केरल में शहरी गरीबों के हित में 5,082 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी।

> मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से शहरी गरीबों के लिए किफायती मकानों के निर्माण हेतु अति शीघ्र प्रस्ताव पेश करने को कहा है, ताकि परिकल्पना के मुताबिक वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 'सभी के लिए मकान' के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से शहरी गरीबों के लिए किफायती मकानों के निर्माण हेतु अति शीघ्र प्रस्ताव पेश करने को कहा है, ताकि परिकल्पना के मुताबिक वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 'सभी के लिए मकान' के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन) डॉ. नंदिता चटर्जी ने केंद्रीय स्क्रीनिंग और निगरानी समिति की बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से उनके द्वारा किये गये नवीनतम मांग आकलन के मुताबिक ही शीघ्र प्रस्ताव पेश करने का आग्रह किया।

इस बैठक के दौरान आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 2,956.32 करोड़ रुपये के निवेश के साथ तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के हित में 78,703 किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी दी। इन मकानों के निर्माण के लिए 1,180.54 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। ■

'मोदी सरकार की कृषि समर्थित नीतियों से किसानों को लाभ पहुंचा'

किसानों के समक्ष सामयिक मुद्दों पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद श्री वीरेन्द्र सिंह 'मस्त' ने कमल संदेश के एशोसिएट एडीटर विकाश आनंद से बातचीत की। उत्तर-प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कृषि संबंधी मुद्दों से रूबरू कराने हेतु 'गांव चलो अभियान' का शुभारम्भ किया। इस साक्षात्कार में उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार किए गए कार्यों से किसानों के जीवन में आए बदलाव पर चर्चा की। 'कमल संदेश' के सुधी पाठकों के लिए इस साक्षात्कार के मुख्य अंशों को प्रकाशित कर रहे हैं।

विमुद्रीकरण का किसान पर क्या असर पड़ा है?

वास्तव में विमुद्रीकरण शास्त्रसम्मत सनातन परंपरा के अनुसार है। समाज को अपव्ययी नहीं होना चाहिए। शास्त्र ने हमें संदेश दिया है। कृपण तो नहीं होना चाहिए। मितव्ययी होना चाहिए, अपव्ययी नहीं। विमुद्रीकरण ने हमारे देश को फिजूल खर्ची से रोक दिया है। यह बहुत बड़ा काम है। जहां तक किसानों का सवाल है। रबी की बुआई ठीक से हुई। तेलहन की बुआई उससे पहले हो चुकी है। सिंचाई हो रही है। कुछ बिजली से सिंचाई होनी हैं, कुछ नहरों से कुछ सोलर पम्प से होने हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत सोलर पम्प से सिंचाई की भी योजना है। अपने यहां सबसे ज्यादा धूप होती है। सोलर पम्प को का इस्तेमाल किया जाय, तो खेती में लागत 45 प्रतिशत कम हो जाएगी। हमारी समझ से अभी तक ऐसी व्यवस्था 10 प्रतिशत ही हो पायी हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत सब्सिडी देकर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका लाभ क्या होगा कि जिस खेत में एक फसल की खेती होती थी उसमें दो फसलों की खेती होने लगेगी।

अभी रबी की बुआई हुई है। क्यों उन्हें बीज, खाद और दूसरी चीजों कोई समस्या हुई?

कुछ लोग विमुद्रीकरण का विरोध यह कहकर करते हैं कि इसका नकारात्मक असर किसानों पर, गरीबों पर पड़ा है। लेकिन सच तो यह है कि किसान और गरीबों पर नहीं पड़ा है। जो कहते हैं उन पर पड़ा है। चूंकि जो ब्लैकमनी, सरकारी खजाना से उन्होंने जमा किया है वह पैसा अब बेकार हो गया। पूरे देश में विभिन्न प्रकार की खेती होती है। केरल में अलग तरह की खेती होती है, उड़ीसा में भी अलग तरह की खेती होती, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में अलग तरह की खेती होती है। राहुल गांधी को लगता है कि देश में सब जगह एक ही तरह खेती होती है, जो गेहूं-बाजरा की फसल को पहचान नहीं सकते वो क्या किसान की बात करेंगे। राहुल जी तो आलू पैदा करने की फैक्ट्री लगवा रहे थे। विमुद्रीकरण का कदम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, समरस समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उठाया गया है।

दरअसल, एक समय जीडीपी में खेती का सबसे बड़ा योगदान होता था अब वह घटता जा रहा है। आप इसका क्या कारण मानते हैं?

आजादी के समय से बजट में खेती को जो हिस्सा दिया जा रहा था, वह धीरे-धीरे घटता ही चला गया। आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आयी है जो बजट का 42 प्रतिशत ग्रामीण और खेती के विकास लिए दी है। 60 वर्ष की बिगड़ी व्यवस्था को ढाई वर्ष में पूरी तरह से ठीक कर दी जाए, ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। शुरू में पंडित नेहरू ने विदेशी मानसिकता से काम किया। वे भूल गए कि भारत की बहुसंख्य जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि को बढ़ावा देने के जगह पर उन्होंने बड़े-बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। यदि वे किसान को मजबूत बनाते तो किसान का बेटा अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण उद्योग धंधा भी खड़ा करता। लेकिन अब देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारतीय दर्शन से प्रभावित है, क्योंकि यह नीति देश की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाते हैं।

कृषि अलाभकारी व्यवसाय होने के कारण लोग इसे छोड़ कर अन्य रोजगारों में पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति के बदलाव के लिए क्या किया जाना चाहिए।

कृषि अलाभकारी व्यवसाय कैसे हैं। कौन सा ऐसा कारखाना है जो दूध

पैदा कर दे, फल पैदा कर दे, अनाज पैदा कर दे। केवल खेती ही भारत के लोगों की जीवनधारा है। लोग खेती को जीते हैं। किसानों को सरकार से सिर्फ यह अपेक्षा है वे जो रेवेन्यू देते हैं उनका उनके विकास में अच्छी तरह से उपयोग हों। किसान बहुत धैर्यशाली, संकल्पशक्ति वाला समुदाय है।

खेती अलाभकारी है क्योंकि दशकों तक सरकार की नीतियों में कृषि उपेक्षित रहा है। अलाभकारी का मतलब आर्थिक लाभ कम। खेती को केवल आप आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं देख सकते। यह किसानों के आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक-राजनैतिक समृद्धि भी है।

गांव से शहर की ओर पलायन को कैसे रोका जा सकता है?

कृषि ऐसा स्रोत है जहां रोजगार की असीम संभावना है। अभी तक उचित तरीके से शासन की ओर से इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया था। अब दिया जा रहा है। सरकार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम (NAM), सॉयल हेल्थकार्ड राष्ट्रीय कामधेनू प्रजनन केन्द्र इत्यादि की योजना शुरू की है। अब सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर रही है।

कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए?

नहीं, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं, उद्योग जैसे सुविधायें दी जानी चाहिए। जिस तरह औद्योगिक विकास के तरफ ध्यान दिया गया, उस तरह कृषि के विकास की तरह ध्यान नहीं दिया गया, जो कि अब सरकार दे रही है।

फसल कम हो या ज्यादा दोनों ही परिस्थितियों में पैसा बिचैलिया ही बटोरता है।?

किसान के लिए समर्थन मूल्य की जगह पर लाभकारी मूल्य होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि लाने-ले जाने का लागत कम हो। एक अनाज के दो बार ट्रांसपोर्टेशन से खर्चे बढ़ जाते हैं।

जैसे हमारे भदोही का अनाज पहले लखनऊ जाएगा फिर वहां से वितरण के लिए भदोही आएगा। लागत कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर भण्डारण और वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। चीजों पर ध्यान देकर कृषि को और बेहतर बना सकते हैं। एक फसली खेती हमारे देश 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक है। यदि सस्ती सिचांई की व्यवस्था हो जाए, एक फसल से दो फसल होने लगेंगी।

कृषि के अलाभकारी होने की वजह से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। संयुक्त परिवार संस्था टूट रही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को गांव से गांव को जोड़ने के साथ-साथ गांव को खेत से भी जोड़ने का सुझाव हमने दिया है। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांव से खेत को जोड़ने का भी प्रावधान हो गया है। जब खेत में आवा-जाही बढ़ जाएगी तो पैदावार भी बढ़ जाएगी। इससे किसान का ध्यान फसल पर अधिक हो जाएगा।

खेती केवल अनाज पैदा करने तक नहीं है। खेती का मतलब फल, सब्जी, दूध का उत्पादन भी है। इन उत्पादनों को बिना नुकसान के मण्डी तक पहुंचाने में भी सहायक होंगी सड़क। बुनकर के साथ भेड़ पालन में लगे लोगों के लिए भी योजनाएं होनी चाहिए। इन चीजों तक सोचना आर्थिक विकास है।

सामाजिक विकास के बारे में कह सकता हूं। इस देश का अधिकांश आबादी किसान है। इसकी सामाजिक संरचना में परिवार संस्था है। बाजार के असर में परिवार की संस्था टूट रही है। परिवार के टूटने से परिवार आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से गरीब हो जाता है। इस संस्था को बचाने के लिए सामाजिक तौर के साथ-साथ राजनीतिक तौर भी सोचना चाहिए।

मोदी सरकार किसानों की दशा सुधारने के लिए जो काम किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं।

आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा काम किया है। पहले तेलहन आयात दूसरे देशों से होती थी, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन से काफी दलहन का पैदावार बढ़ी है, मेरे ख्याल से एक-दो साल में आयात बंद हो जाएंगे। दो साल बाद अपने देश का किसान निर्यात करने लगेगा। सरकार ने किसान के हित में वन विंडो प्रणाली लागू किया हैं। मध्य प्रदेश में कम उपजाऊ जमीन है। उत्तर प्रदेश की तुलना में लेकिन वन विंडो प्रोग्राम शिवराज सिंह ने लागू किया है। जिसके वजह से मध्यप्रदेश का कृषि-विकास दर काफी अच्छा है। उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा गंगा-यमुना का मैदान है। दुनिया सबसे उपजाऊ मैदान है। सबसे कम उपज दे रहा है। आज मध्य प्रदेश देश का कृषि का सबसे उन्नतिशील प्रदेश बन गया है, क्योंकि किसान समाज और संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 सालों से शासन के स्तर पर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार है। यदि केन्द्र सरकार किसानों के लिए जितनी योजनाएं बनाती है, उसी को राज्य सरकार सही में लागू करती तो किसान के लिए बहुत बड़ा कार्य हो जाता।

राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम गांवों में कितना सफल है।

स्वच्छता हमारी संस्कृति की श्रेष्ठ परंपरा रही है। मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लोगों के स्मृति में लाया है कि हमारी देश की परंपरा में स्वच्छता महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरह से मोदी जी इसे आंदोलन का रूप दे दिया है। मोदी जी पर लोगों का इतना भरोसा है कि इनसे प्रेरित होकर गांव-गांव इस आंदोलन में शामिल हैं। मोदी जी के आह्वान पर 5 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। परिणामस्वरूप 10 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला। इसके पहले अनाज और लोगों को मिले इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने सोमवार को उपवास रहने का आह्वान किया था। और देश की जनता आह्वान प्रेरित होकर सोमवार को उपवास रखे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया।

किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम कब तक बनने की संभावना है।

देश प्रदेश स्तर पर किसान मोर्चा बहुत बड़ी संरचना है। बातचीत चल रही है। चुनाव 5 प्रदेशों में हो रहे हैं। जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ■

पांच राज्यों में चुनाव

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव आसन्न हैं। चार फरवरी से आठ मार्च के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधान सभा चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। चार फरवरी को पंजाब और गोवा में एक चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। मणिपुर में दो चरणों में चार मार्च और आठ मार्च को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से आठ मार्च के बीच सात चरणों में मतदान होगा।
आइए, जानते हैं इन राज्यों में दलीय स्थिति क्या है और कौन से मुद्दे चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभा सकते हैं।

वर्तमान दलगत स्थिति

पंजाब

पार्टी	सीटें
शिरोमणि अकाली दल	54
भारतीय जनता पार्टी	11
कांग्रेस	48
निर्दलीय	03
रिक्त	01
कुल	**117**

प्रमुख मुद्दे – विकास, बेरोजगारी और नशे की समस्या

उत्तर प्रदेश

पार्टी	सीटें
समाजवादी पार्टी	229
बहुजन समाज पार्टी	80
भारतीय जनता पार्टी	41
कांग्रेस	28
राष्ट्रीय लोक दल	08
पीस पार्टी	04
कौमी एकता दल	02
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	01
अपना दल	01
इत्तेदाह-ए-मिल्लत	01
निर्दलीए	06
रिक्त	02
कुल	**403**

प्रमुख मुद्दे – भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की समस्या और विकास

उत्तराखंड

पार्टी	सीटें
कांग्रेस	26
भाजपा	28
पीडीएफ	06
निलंबित	10*
कुल	**70**

* कांग्रेस के 9 और भाजपा के एक बागी की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की। मामला न्यायालय के विचाराधीन।

प्रमुख मुद्दे – पर्यावरण को हो रही क्षति, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार

मणिपुर

पार्टी	सीटें
कांग्रेस	42
एआईटीसी	07
एमएससीपी	05
नगा पीपुल्स फ्रंट	04
एनसीपी	01
एलजेपी	01
कुल	**60**

प्रमुख मुद्दे – आफ्सपा कानून, बंद एवं चक्काजाम और आदिवासियों बीच आपसी संघर्ष

गोवा

पार्टी	सीटें
भाजपा	21
कांग्रेस	09
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी	03
निर्दलीय	05
गोवा विकास पार्टी	02
कुल	**40**

प्रमुख मुद्दे – विकास, सामुदायिक पहचान और भाषायी पहचान

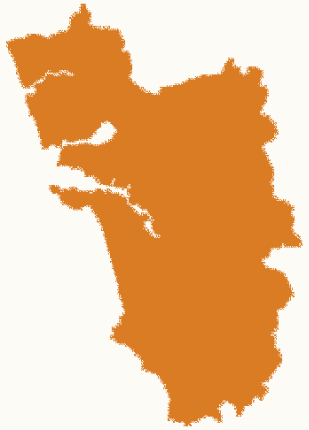

डिजिटल भुगतान को मिला प्रोत्साहन

3.81 लाख से अधिक ग्राहकों और 21,000 व्यापारियों ने 60.90 करोड़ रुपये के पुरस्कार जीते

विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान प्रणाली और कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना में विभिन्न आयु वर्गों, व्यवसायों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं।

19 जनवरी तक देश भर में 24 डिजि-धन मेलों के दौरान 3.81 लाख ग्राहकों और 21 हजार व्यापारियों को 60.90 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि का विजेता घोषित किया जा चुका है। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सामान्य सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स) ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के जरिए लेनदेन करने के लिए 1.94 करोड़ नागरिकों और 5.93 लाख व्यापारियों को प्रशिक्षित किया है।

> इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सामान्य सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स) ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के जरिए लेनदेन करने के लिए 1.94 करोड़ नागरिकों और 5.93 लाख व्यापारियों को प्रशिक्षित किया है।

नीति आयोग की लकी ड्रा योजना में ग्राहकों के लिए 'लकी ग्राहक योजना, एलजीवाई' और व्यापारियों के लिए 'डिजि-धन योजना, डीवीवाई' के तहत देश भर में 24 डिजि-धन मेलों के दौरान दैनिक/साप्ताहिक आधार पर 3.81 लाख से अधिक विजेताओं को 60.90 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जा चुकी है। विजेता सूची में छोटे किसानों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, गृहिणियों, मजदूरों आदि समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान को अपनाए जाने को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक उन शीर्ष पांच राज्यों में हैं, जहां विजेताओं की संख्या सबसे अधिक है। पुरुषों एवं महिलाओं का इसमें सक्रिय सहभागिता देखने को मिली है। इस योजना के ज्यादा विजेता 21 से 30 वर्ष की आयु के हैं।

इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ 25 मार्च, 2016 को हुआ था। ये योजनाएं 14 अप्रैल, 2017 तक चलेंगी। इन योजनाओं का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करना है। 15,000 विजेता प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि पाएंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, 14,000 विजेता साप्ताहिक ड्रा के लिए क्वालिफाई

करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लिए कुल पुरस्कार राशि 8.3 करोड़ रुपये होगी।

रूपे कार्ड, भीम यूपीआई (भारत इंटरफेस फॉर मनी/यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस), यूएसएसडी आधारित *99# सेवा और आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक और व्यापारी दैनिक और साप्ताहिक लकी ड्रा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे।

ये लकी ड्रा देश भर में आयोजित होने वाले डिजि-धन मेले में निकाले जाएंगे। लोगों के मस्तिष्क में डिजिटल भुगतान को बैठाने के लिए देश भर में 100 से अधिक डिजि-धन मेला आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर, 2016 से अब तक देश भर में 24 डिजि-धन मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें नई दिल्ली, गुरुग्राम, लुधियाना, पणजी, देहरादून, लखनऊ, रांची, रायपुर, मुंबई, मेरठ, हल्द्वानी, अमृतसर, पुणे, पटना, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोच्चि, बिलासपुर, बोकारो, दादरा एवं नगर हवेली, बेंगलुरू, जम्मू और हैदराबाद शामिल हैं। इसमें अब तक 12 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। पहली फरवरी से, यह कवायद 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। ■

पृष्ठभूमि

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय वित्त एवं कंपनी मामले मंत्री श्री अरुण जेटली और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 25 दिसंबर, 2016 को लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। 14 अप्रैल, 2017 तक देश भर के 100 विभिन्न शहरों में 100 डिजिधन मेलों में लकी ड्रा निकाले जाएंगे। इस योजना मुख्य बातें इस प्रकार हैं -

- इस योजना के तहत ग्राहकों और व्यापारियों द्वारा नौ नवंबर, 2016 से 14 अप्रैल 2017 के बीच किया जाने वाला सभी डिजिटल लेनदेन पुरस्कार जीतने के लिए पात्र होगा।
- ऐसे सभी लेनदेन जिन्होंने दैनिक/साप्ताहिक पुरस्कार जीता हो, 14 अप्रैल, 2017 को होने वाले मेगा ड्रा के लिए भी पात्र होंगे।
- ग्राहकों के लिए एक करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के तीन मेगा पुरस्कार हैं।
- व्यापारियों के लिए भी 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के तीन मेगा पुरस्कार रखे गए हैं।
- भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति आयोग के प्रतिनिधियों और आम लोगों की मौजूदगी में एनपीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग केंद्रों पर हर दिन के ड्रा के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे।
- इस योजना का कुल बजट 340 करोड़ रुपये रखा गया है। इनमें से 300 करोड़ रुपये ग्राहकों और व्यापारियों पर खर्च किए जाएंगे जबकि शेष 40 करोड़ रुपये की राशि जागरुकता और प्रचार के लिए खर्च की जाएगी।
- इस योजना के कुल विजेताओं की संख्या 18.75 लाख से ऊपर जाने की संभावना है।

'गुरु गोबिंद सिंह ने अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों से देश पर बड़ा उपकार किया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 8 जनवरी को जबलपुर (मध्य प्रदेश) के शिवाजी मैदान में आयोजित गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज बहुत ही पवित्र मौक़ा है, आज हम सब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के वर्ष में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों से देश पर बहुत बड़ा उपकार किया, इस तरह की मिसालें इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का जोड़ मिलना बहुत मुश्किल है, ईश्वर भी एक ही व्यक्ति में अनेकों प्रकार के गुण बहुत कम ही देता है, ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्त्व था उनका। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी एक साथ ही एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक युगपुरुष थे।

श्री शाह ने कहा कि निस्संदेह गुरु गोबिंद सिंह जी अपने काल-खंड के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, उन्होंने एक भाषा में नहीं बल्कि संकृत, ब्रज, गुरुमुखी, हिन्दी, फारसी - कई भाषाओं में साहित्य की रचना की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पटना में जन्म लेता है, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करता है और वह ब्रज बोली के शुद्धिकरण का काम करता है, कितना यशस्वी वक्तित्त्व होगा उनका।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वीरता में गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी नहीं था, उनके जैसा योद्धा सहस्र सालों में शायद ही कभी पैदा होता है, उनकी वीरता के जितने भी गुण गाये जाएँ, वे कम हैं। जब एक 9 साल का बच्चा गुरु तेग बहादुर जैसे प्रचंड व्यक्तित्त्व वाले अपने पिता को देश-हित में आत्म-बलिदान की प्रेरणा देता है, तभी मालूम पड़ जाता है कि वह बच्चा गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। उन्होंने कहा कि देश के हजारों सालों के इतिहास में एक ही वीर बलिदानी ऐसा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हँसते-हँसते अपने चारों बेटों का बलिदान दे दिया, उनके चार पुत्रों में से दो साहबजादे चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए जबकि दो बेटों को दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया गया। एक मार्मिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा, "जब छोटे बेटे को दीवार में चुनवाया जा रहा था तो अपने बड़े भाई की आँखों में आंसू देख उन्होंने उनसे पूछा कि हम सिंह की संतान है, फिर आँखों में आंसू क्यों तो बड़े भाई ने जवाब दिया कि धर्म के रास्ते

पर पहले बड़े भाई के बलिदान के बदले छोटे का बलिदान हो रहा है, इसलिए मेरी आँखों में आंसू आ गए। अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई थी लेकिन ये वीरता भरी वाणी गुरु गोबिंद सिंह जी के सुपुत्रों की ही हो सकती है और किसी की नहीं।"

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि खालसा पंथ की स्थापना करके देश की रक्षा करने का काम जो दशम गुरु ने किया है, देश उसको कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर के एक साथ कई काम किये, उन्होंने सिखों को वीरता की प्रेरणा दी, देश को स्वतंत्रता एवं आध्यात्मिकता का संदेश दिया, दसों गुरुओं की गुरुवाणी को शब्द देने का काम भी उन्होंने ही किया, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को अक्षुण रखने के साथ-साथ उन्होंने जाति-पाति के भेद-भाव को मिटाने का काम भी उन्होंने ही किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश के अलग-अलग हिस्से से, अलग-अलग जाति और सम्प्रदाय से पंच-प्यारे पसंद करके राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का अलख जगाने का काम किया ताकि देश, धर्म और समाज पर जो विपत्ति आन पड़ी है, उसका डटकर मुकाबला किया जा सके। आज उनके द्वारा स्थापित वही पंथ इतने सालों बाद भी देश और दुनिया को एकता और ज्ञान का प्रकाश दे रहा है।

> गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन इतना प्रकाश फैलाता है कि 350 साल बाद भी वह प्रकाश आज भारत को चकाचौंध कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है कि एक व्यक्ति का जीवन ऐसा सरल और यशस्वी कैसे हो सकता है।

श्री शाह ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांच 'क' के माध्यम से देश और समाज को एक साथ एकता, स्वछता, दृढ़ता, संयम और वीरता का संदेश दिया जो हमारे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है कि किस तरह से हमें मिल-जुल कर रहना चाहिए और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लोग आज जहां कहीं भी हैं, वे घुल-मिलकर समानता में विश्वास के साथ रहते हैं। ■

राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2016

मछुवारों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में सहायक

देश में समुद्री मात्स्यिकी में मौजूदा असंतुलन दूर करने तथा इससे जुड़े लाखों मछुवारों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2016' एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के फिशरीज मंत्रियों के साथ "राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2016" पर आयोजित बैठक में प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि तट से दूर गहरे समुद्र में मौजूदा समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग और लाखों मछुआरों की आजीविका को सुगम बनाने के लिए जरूरी है कि केन्द्र और तटीय राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति पर पूरी गंभीरता के साथ अमल करें। कृषि मंत्री ने यह बात 13 जनवरी को कृषि मंत्रालय में तटीय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के फिशरीज मंत्रियों के साथ 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति – 2016" पर हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद कही। साथ ही पारम्परिक मछुवारों को गहरे-समुद्र में फिशिंग की ट्रेनिंग देने की दिशा में पहले ही प्रयास शुरू कर दिये गये हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि देश में समुद्री मात्स्यिकी में मौजूदा असंतुलन दूर करने में, इसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में तथा इससे जुड़े लाखों मछुवारों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2016 ' एक अहम मार्गदर्शक की भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि देश में निकटवर्ती समुद्री संसाधनों का पिछले दो तीन दशकों में अधिक दोहन हुआ है। यह सिलसिला अगर इसी प्रकार से जारी रहा तो आने वाले कुछ वर्षों मे समुद्री आजीविका पर संकट आ सकता है। उन्होंने कहा कि ईईजेड के गहरे समुद्री संसाधन अभी भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। इस संकट से निकलने के लिए जरूरी है कि समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत उत्पादन को बनाये रखा जाए।

कृषि मंत्री ने बैठक में कहा कि प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति' के मसौदे मे वर्तमान मे गहरे-समुद्र मे फिशिंग करने सम्बंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किये जाने वाले Letter of Permission (LOP) regime को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर पारम्परिक मछुवारों को गहरे-समुद्र में फिशिंग की ट्रेनिंग और कौशल विकास द्वारा सशक्तिकरण करने सम्बंधी सिफारिश की गयी है। उन्होंने कहा कि पारम्परिक मछुवारों को गहरे-समुद्र मे फिशिंग की ट्रेनिंग देने की दिशा में पहले ही प्रयास शुरू कर दिये गये हैं, तथा पारम्परिक मछुवारों द्वारा गहरे-समुद्र मे फिशिंग को बढावा देने के लिये विशेष योजना शुरू करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति' के मसौदे में यह प्रस्ताव भी है कि सरकार/मंत्रालय द्वारा इस 'नीति' के मसौदे की औपचारिक स्वीकृति के बाद मसौदे में निहित प्रत्येक सिफारिश पर कार्रवाई के लिये, आगामी दस वर्षों के लिये एक विस्तृत 'रोड-मैप' बनाया जायेगा। इस 'रोड-मैप' में विभिन्न सिफारिशों पर कार्रवाई के लिये न केवल जिम्मेदार एजेंसियों को चिन्हित किया जायेगा, बल्कि कार्यान्वयन की समय-अवधि भी तय की जायेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि इसके अलावा नीति के कार्यान्वयन के लिये जरूरी धन के सम्भावित स्रोत निर्दिष्ट करने के सुझाव भी 'रोड-मैप' में दिये जायेंगे। कार्यान्वयन योजना की समय बद्धता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये 'निगरानी और मूल्यांकन' की रूपरेखा भी बनाई जायेगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि 'मात्स्यिकी' मूल रूप से राज्य-सरकार का विषय है। अंतःस्थलीय मात्स्यिकी (Inland Fisheries) तथा 12 समुद्री-मील तक का क्षेत्र पूर्णरूप से राज्यों के ही अधीन आता है, जबकि 12 समुद्री-मील से परे, 200 समुद्री-मील तक का 'ई.ई.जेड' का क्षेत्र ही केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि 'समुद्री-मात्स्यिकी' मे 0 से 200 समुद्री-मील तक के सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास को दिशा देने के मकसद से, वर्तमान में लागू 'व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति' को वर्ष 2004 में जारी किया गया था। इस नीति के तहत तटवर्ती राज्यों और केंद्र, दोनों को मिल कर देश में 'समुद्री-मात्स्यिकी' के विकास के प्रयास करने थे। चूंकि इस नीति को जारी किये 10 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था, इसलिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के बदलते परिप्रेक्ष्य में देश की 'समुद्री मात्स्यिकी नीति' की समीक्षा करना आवश्यक था।

इस बैठक में महाराष्ट्र के फीशरीज मंत्री श्री जंकार महादेव जगन्नाथ तथा तमिलनाडु के फीशरीज मंत्री श्री डी. जयकुमार के साथ गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं समुद्री मात्स्यिकी नीति के मसौदा समिति के अध्यक्ष डा. एस. अयप्पन ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा एलओपी स्कीम समाप्त करने का आग्रह किया। साथ ही, तटीय क्षेत्रों में एक समान फीशिंग बैन लगाने का सुझाव दिया। सभी राज्यों ने प्रस्तावित समुद्री मात्स्यिकी नीति का स्वागत किया। ■

राष्ट्रीय युवा महोत्सव, रोहतक

काले धन की लड़ाई में सबसे ज्यादा युवाओं ने साथ दिया: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने युवाओं को 3-सी का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि युवा कलेक्टिविटी, कनेक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर ध्यान दें, क्योंकि देश के युवा ही देश को नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा की ये धरती वेदों की है, उपनिषदों की है, गीता की है। ये वीरों की कर्म-वीरों की है, जय जवान-जय किसान की धरती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को रोहतक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत युवाओं को युवा दिवस की शुभकामनाओं से की और इसके बाद स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग को युवाओं, उनके प्रदेश, देश और पूरी दुनिया के लाभकारी बताया। इस दौरान उन्होंने युवाओं का धन्यवाद किया और कहा कि कालेधन की लड़ाई में सबसे ज्यादा साथ देश के युवाओं ने दिया। श्री मोदी ने कहा देश की 80 करोड़ आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की आयु के युवाओं की है। उन्होंने कहा, 'युवा डिजिटल इंडिया बनाने में सहयोग करें।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभांकर बेटी के रूप में चुना गया है। दुलार से इसे नाम दिया गया है ''म्हारी लाडो'। इस महोत्सव के माध्यम से ''बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हरियाणा से ही केंद्र सरकार ने ''बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का इस क्षेत्र में बड़ा असर दिख रहा है। बदलाव की शुरुआत हुई है। सेक्स रेश्यो में काफी बदलाव आया है। पूरे देश के लिये ये बदलाव बढ़ रहा है। मैं हरियाणा के लोगों को इसके लिए खास तौर पर बधाई देता हूं। ये दर्शाता है कि जब लोग ठान लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही पूरे देश के लिये गौरवपूर्ण स्थिति हरियाणा निर्माण करके दिखाएगा।

यही नहीं, प्रधानमंत्री ने युवाओं को 3-सी का मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि युवा कलेक्टिविटी, कनेक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर ध्यान दें, क्योंकि देश के युवा ही देश को नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा की ये धरती वेदों की है, उपनिषदों की है, गीता की है। ये वीरों की कर्म-वीरों की है, जय जवान-जय किसान की धरती है। ये सरस्वती की पावन धरा है। अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को सहेजकर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास, ये इस धरती से सीखा जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती। मैं आप सभी के माध्यम से देश के हर नौजवान को इस विशेष दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद इस बात का सबसे उत्तम उदाहरण हैं कि अल्प अवधि में भी कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन बहुत कम समय का था। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के असीम प्रेरक हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे- हमारे देश को इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह की दृढ़ इच्छा-शक्ति-संपन्न युवाओं की।

उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ऐसे युवाओं का निर्माण करना चाहते थे, जिनमें बिना भेद-भाव के एक दूसरे के प्रति प्रेम व विश्वास हो। युवा वह होता है, जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। आप सभी युवा जो काम आज करते हैं, वही तो कल जाकर देश का भविष्य बन जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की आयु इस समय 35 वर्ष से कम है। स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलकर के आज भारत में एक ऐसे युग की शुरुआत करने की क्षमता है, जो विश्व गुरू बन सकता है।

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है- यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। इस महोत्सव के माध्यम से युवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल तरीके से लेन-देन की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरी इस महोत्सव में ट्रेनिंग लेने वाले हर युवा से अपील है कि जब वो यहां से ट्रेनिंग लेकर जाएं तो अपने आसपास के कम से कम 10 परिवारों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करना सिखाएं। लेसकैश अर्थव्यवस्था बनाने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। देश को कालेधन और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई में ये आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

श्री मोदी ने कहा कि हरियाणा के भविष्य को संवारने में यहां का युवा वर्ग एक बड़ी भूमिका निभा रही है। हरियाणा के युवा खिलाड़ियों ने अनेक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल कर सदा-सर्वदा पूरे देश का मान बढ़ाया है। पूरे देश में विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए युवा शक्ति के और अधिक योगदान की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य अपने युवकों को, इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए क्षमताएं एवं कौशल प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप सभी को अपनी प्रतिभा के प्रर्दशन के लिए एक मंच प्रदान करता है। अलग-अलग सांस्कृतिक परिवेश से आए हुए आप सभी नौजवानों को यहां एक दूसरे को जानने का समझने का मौका मिलेगा। यही तो एक भारत-श्रेष्ठ भारत का वास्तविक अर्थ है।

श्री मोदी ने कहा कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत एक प्रयास है देश की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का। हमारे देश में भाषाएं भले अलग-अलग हों, खान-पान अलग-अलग हों, रहने का तरीका अलग-अलग हो, रीति-रिवाज अलग-अलग हों, लेकिन आत्मा एक ही है। उस आत्मा का नाम है - भारतीयता। और इस भारतीयता के लिये मैं और आप हम सब गर्व करते हैं।

उन्होंने कहा कि एक राज्य के नौजवान दूसरे राज्य के युवाओं से मिलेंगे तो उन्हें भी नया अनुभव होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। लोग जब साथ रहते हैं, मिलते-जुलते हैं तो समझ आता है कि ये खान-पान और भाषाई अंतर सतही हैं। गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि हमारे मूल्य, हमारी मानवीयता, हमारा दर्शन एक जैसा ही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शताब्दी मना रहा है। देश के नौजवानों के लिए पंडित जी का मंत्र था- चरैवति-चरैवति, चरैवति यानी चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं, राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलते जाना है।

श्री मोदी ने नौजवानों से कहा कि एक दूसरे से संपर्क करिए, सामूहिक जिम्मेदारी निभाना सीखिए और नए विचारों पर काम करिए। अपने नए विचारों को ये सोचकर समाप्त मत होने दीजिए कि ये तो बहुत छोटे हैं या फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे। याद रखिए कि दुनिया में ज्यादातर बड़े और नए विचारों को पहले खारिज ही किया गया है। जो भी मौजूदा सिस्टम होता है, वो नए विचारों का विरोध करता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे देश की युवाशक्ति के आगे ऐसा हर विरोध ठंडा पड़ जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से पचास से भी ज्यादा वर्ष पूर्व एकात्म मानववाद पर बोलते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा था, उसमें भी देश के युवाओं के लिए बड़ा संदेश है। दीन दयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्र निर्माण और देश में मौजूद बुराइयों से लड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था-

"हमें अनेक रूढ़ियां खत्म करनी होंगी। बहुत से सुधार करने होंगे, जो हमारे मानव का विकास और राष्ट्र की एकात्मता की वृद्धि में पोषक हों, वह हम करेंगे और जो बाधक हो, उसे हटाएंगे। ईश्वर ने जैसा शरीर दिया है, उसमें मीनमेख निकालकर अथवा आत्मग्लानि लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, पर शरीर में फोड़ा होने पर उसका ऑपरेशन तो आवश्यक है। सजीव और स्वस्थ अंगों को काटने की जरूरत नहीं है। आज यदि समाज में छुआछूत और भेदभाव घर कर गए हैं, जिसके कारण लोग मानव को मानव समझकर नहीं चलते और जो राष्ट्र की एकता के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, हम उनको खत्म करेंगे"।

श्री मोदी ने कहा कि पंडित जी के ये आह्वान आज भी उतनी ही अहमियत रखता है। आज भी देश में छुआछूत है, भ्रष्टाचार है, कालाधन है, अशिक्षा है, कुपोषण है। इन सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए देश के युवा को अपनी शक्ति झोंकनी होगी। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को जितना समर्थन मेरे नौजवान दोस्तों ने दिया है, वो इस बात का सबूत है कि समाज में व्याप्त बुराई को मिटाने की आप सभी में कितनी जबरदस्त इच्छाशक्ति है। ■

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता

और

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

गोवा में चुनावी जनसभाओं के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

मडगाव

वास्को

पंजाब विधानसभा चुनाव के निमित्त भाजपा चुनाव घोषणा–पत्र जारी करते भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' के हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003